RNI No. MPHIN/2015/64451 डाक पंजीयन क्र. MP/IDC/1525/2022-2024 IPT डाक द्वारा प्रेषण प्रति शुक्रवार indianplasttimes@gmail.com
DPR No. N-193
www.Indianplasttimes.in

इंडियन प्लास्ट टाइम्स

■ INDORE ■ 21 AUGUST TO 27 AUGUST 2024 ■ प्रति बुधवार ■ वर्ष 09 ■ अंक 48 ■ पृष्ठ 8 ■ कीमत 5 रु.

Inside News

कम होगा आपके टैक्स का बोझ! 9 सितंबर को मिल सकती है गुड न्यूज Page 2

हवाला और टेरर फंडिंग में क्रिप्टो के लेन-देन का पता लगाता है इंडियन सॉफ्टवेयर Page 3

सोने की चमक लौटी, बजट के बाद 5 हजार रुपये तक चढ़े भाव; आगे और तेजी के आसार Page 4

editorial!

भोजन में प्लास्टिक

बहुत लंबे समय से हमारे जीवन में प्लास्टिक से बनी चीजों की उपयोगिता रही है, पर अब यह अभिशाप बन गया है. हाल तक प्लास्टिक कचरे के निपटान और उसे फिर से इस्तेमाल लायक बनाने की चुनौती थी, पर अब यह हमारे भोजन को भी प्रदूषित करने लगा है. हाल में एक अध्ययन में पाया गया है कि देश में बिकने वाले नमक और चीनी के सभी ब्रांडों में माइक्रोप्लास्टिक की मौजूदगी है. इस संबंध में भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने एक नयी पहल की है. इस राष्ट्रीय परियोजना में खाद्य पदार्थों में माइक्रोप्लास्टिक की पहचान की जायेगी तथा उसका अध्ययन किया जायेगा. इस पहल का प्रारंभ मार्च में हो गया था. इस प्रयास के निष्कर्षों के आधार पर माइक्रो और नैनो प्लास्टिक के लिए एक दिशा-निर्देश तैयार किया जायेगा. इस परियोजना में अनेक प्रमुख शोध संस्थानों की सहभागिता है. उल्लेखनीय है कि संयुक्त राष्ट्र की संस्था खाद्य एवं कृषि संगठन ने भी अनेक खाद्य पदार्थों में प्लास्टिक होने के संबंध में रिपोर्ट दी है. नालियों और नदियों से बहकर कचरे के समुद्र में पहुंचने से समुद्री जीवों में भी प्लास्टिक प्रदूषण होने लगा है. खाद्य पदार्थों से मानव शरीर में जब यह प्रदूषण पहुंचता है, तो अनेक गंभीर बीमारियों का कारण बनता है. खाद्य प्राधिकरण की परियोजना से खाद्य सुरक्षा में बेहतरी के साथ-साथ प्लास्टिक प्रदूषण के बारे में विस्तृत आंकड़े भी हासिल होंगे, जिससे इसके दीर्घकालिक समाधान को आधार मिल सकता है. एक हालिया जांच में प्राधिकरण ने पाया है कि 12 प्रतिशत भारतीय मसाले मानकों पर खरे नहीं उतरे हैं. कुछ समय यह भी पता चला था कि कई बड़े ब्रांड अपने उत्पादों के बारे में अधूरी जानकारी दे रहे हैं या उनके बारे में भ्रामक दावे कर रहे हैं. अनेक बड़े शहरों में कई नामचीन रेस्तरां नियमों का उल्लंघन करते हुए पाये गये हैं. इस वर्ष अप्रैल में वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने ई-कॉमर्स कंपनियों को अपने एप और वेबसाइट से 'स्वास्थ्य पेय' (हेल्थ ड्रिंक्स) श्रेणी से सभी पेय उत्पादों को हटाने का निर्देश दिया था. उसी माह खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने ई-कॉमर्स कंपनियों को खाद्य उत्पादों का समुचित श्रेणीकरण सुनिश्चित करने का निर्देश दिया था. यह भी पाया गया है कि नुकसानदेह मैदा, चीनी और रिफाइंड तेल में बने बिस्किट उत्पादों को स्वास्थ्यवर्धक कह कर बेचा जा रहा है. किसी वस्तु में इस्तेमाल सामग्री तथा उनसे मिलने वाले पोषण से संबंधित सूचनाओं को आम तौर पर इतने महीन अक्षरों में छापा जाता है कि लोगों का ध्यान ही नहीं जाता. चीनी, नमक, वसा जैसे तत्वों की अधिकता से कई बीमारियां हो रही हैं. प्राधिकरण और खाद्य विभागों को अधिक सक्रियता दिखाते हुए मिलावट और प्रदूषण की रोकथाम को प्राथमिकता देनी चाहिए. ग्राहकों को भी अधिक सचेत होना चाहिए.

राज्यों की लगी लॉटरी

माइनिंग कंपनियों को लगेगा 1.5 लाख करोड़ का झटका

नई दिल्ली। एजेंसी

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को माइनिंग रॉयल्टी पर बड़ा फैसला दिया। सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों को 1 अप्रैल 2005 के बाद से केंद्र सरकार और खनन कंपनियों से खनिज संपन्न भूमि पर रॉयल्टी का पिछला बकाया वसूलने की अनुमति दे दी। सरकारी और निजी क्षेत्र की खनन कंपनियों पर 1.5 लाख करोड़ रुपये का बकाया है। कोर्ट के इस फैसले से खनिज संपदा वाले राज्यों को फायदा होगा। कोर्ट ने कहा कि केंद्र और खनन कंपनियां अगले 12 वर्ष में क्रमबद्ध तरीके से राज्यों को बकाये का भुगतान कर सकती हैं। हालांकि कोर्ट ने खनिज संपन्न राज्यों को रॉयल्टी के बकाये के भुगतान पर किसी तरह का जुर्माना न लगाने का निर्देश दिया है। इस फैसले से ओडिशा, झारखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान जैसे राज्यों को फायदा होगा।सरकारी और निजी क्षेत्र की खनन कंपनियों पर राज्यों का 1.5 लाख करोड़ रुपये का बकाया है। आधिकारिक अनुमानों के अनुसार सरकारी कंपनियों पर 70,000-80,000 करोड़ रुपये का बकाया है। सरकारी स्टील कंपनी सेल पर 3,000 करोड़ रुपये का बकाया है। टाटा स्टील

पर राज्यों का 17,347 करोड़ रुपये बकाया है। एनएमडीसी के चेयरमैन अमिताभ मुखर्जी ने कहा कि इस फैसले का खनन उद्योग पर व्यापक असर पड़ेगा। कोर्ट के इस फैसले का सरकारी कंपनी कोल इंडिया पर और अधिक बोझ पड़ेगा। कंप्टीशन बढ़ने और मार्जिन घटने से उसकी मुश्किलें बढ़ती जा रही है। इससे कंपनी के आधुनिकीकरण और विस्तार पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।

ओडिशा नंबर वन

देश के कुल खनिज उत्पादन में ओडिशा की हिस्सेदारी करीब 44ℨ है। इसके साथ ही झारखंड, छत्तीसगढ, केरल और राजस्थान भी खनिज उत्पादन में काफी आगे हैं। भारत में दो तरह के मिनरल्स पाए जाते हैं। इनमें मेटालिक और नॉन-मेटालिक मिनरल्स शामिल हैं। मेटालिक मिनरल्स वे होते हैं जिनसे सोना, चांदी, कॉपर, जिंक और एल्युमीनियम जैसी धातुएं निकाली जाती हैं। नॉन-मेटालिक मिनरल्स में सैंड, जिप्सम, यूरेनियम आदि आते हैं। ओडिशा को भारत को मिनरल्स स्टेट कहा जाता है। राज्य में सभी तरह के मिनरल्स प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। इनमें लौह अयस्क, मैगनीज, क्रोमाइट, बॉक्साइट और लाइमस्टोन शामिल हैं। इसके साथ ही ओडिशा में कोयले का भी बड़ा भंडार है।

क्या है रॉयल्टी

कंपनियां खनिज की मात्रा के अनुपात में निकाले गए खनिज के लिए एक निश्चित राशि का भुगतान करना होता है। इस तरह के भुगतान को रॉयल्टी कहा जाता है। रॉयल्टी की गणना निकाले गए या हटाए गए खनिजों की मात्रा के आधार पर की जाती है। केंद्र सरकार के आंकड़ों के मुताबिक साल 2021-22 में मिनरल्स से सबसे ज्यादा 1798369.46 लाख रुपये की रॉयल्टी ओडिशा की बकाया थी। 2020-21 में यह आंकड़ा 703461.83 लाख रुपये था। इसी तरह छत्तीसगढ़ का 2021-22 में 883872.12 लाख रुपये, राजस्थान का 367596.65 लाख रुपये, झारखंड का 279140.34 लाख रुपये और आंध्र प्रदेश का 41402.136 लाख रुपये मिनरल्स की रॉयल्टी के रूप में बकाया था।

यूपी का कितना बकाया

कर्नाटक का 254214 लाख रुपये, महाराष्ट्र का 30453.66 लाख रुपये, गुजरात का 25165.11 लाख रुपये, तेलंगाना का 22473.79 लाख रुपये, तमिलनाडु का 17936.39 लाख रुपये और गोवा का 9755.24 लाख रुपये की रॉयल्टी बकाया थी। उत्तर प्रदेश का 2452.32 लाख रुपये का बकाया था। इसे विडंबना ही कहा जाएगा कि झारखंड के पास देश में कोयले का सबसे बड़ा भंडार है लेकिन बिजली की उपलब्धता के मामले में यह सबसे नीचे स्थित पांच राज्यों में शामिल है।

सरकार का फैसला

देश को मिलेंगे तीन नए मेट्रो प्रोजेक्ट

दो नए एयरपोर्ट प्रोजेक्ट को भी मिली मंजूरी

नई दिल्ली। आईपीटी नेटवर्क

शुक्रवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मेट्रो के तीन नए प्रोजेक्ट और दो नए एयरपोर्ट प्रोजेक्ट को मंजूरी दी। इन फैसलों के बारे में जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि देश को दो नए एयरपोर्ट को मंजूरी मिली है। वहीं तीन मेट्रो प्रोजेक्ट को भी मंजूरी दी गई है। इनमें बेंगलुरु, ठाणे और पुणे के लिए मेट्रो प्रोजेक्ट शामिल हैं। दो नए एयरपोर्ट पश्चिम बंगाल और बिहार में बनेंगे।

रेलवे के 8 बड़े नए प्रोजेक्ट को मिली मंजूरी, 3 करोड़ नए घर बनेंगे, मोदी सरकार का बड़ा फैसला

ये हैं तीन नए मेट्रो प्रोजेक्ट

1. बेंगलुरु मेट्रो रेल प्रोजेक्ट

बेंगलुरु मेट्रो प्रोजेक्ट के तहत दो नए कॉरिडोर को भी मंजूरी मिली है। इसमें पहला कॉरिडोर जेपी नगर (चौथा फेज) और कम्पापुरा के बीच होगा। वहीं दूसरा कॉरिडोर होसाहल्ली और कड़बगेरे के बीच होगा। इस प्रोजेक्ट में 15611 करोड़ रुपये खर्च होंगे।

2. ठाणे रिंग मेट्रो रेल प्रोजेक्ट

यह एक रिंग प्रोजेक्ट होगा। इसकी लंबाई 29 किलोमीटर होगी। इसके 2029 तक शुरू होने की उम्मीद है। इस प्रोजेक्ट में 12200 करोड़ रुपये खर्च होंगे।

3. पुणे मेट्रो फेज-1

कैबिनेट में पुणे मेट्रो के पहले फेज को भी मंजूरी दी। यह प्रोजेक्ट स्वारगेट से कात्रज की ओर होगा। इसकी लंबाई 5.46 किलोमीटर होगी। इस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए 2954.53 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं।

ये हैं दो नए एयरपोर्ट प्रोजेक्ट

1. पश्चिम बंगाल के सिलिगुड़ी स्थित बागडोगरा एयरपोर्ट पर एक नया सिविल एन्कलेव बनेगा। इसे बनाने में करीब 1549 का खर्चा आएगा जिसकी मंजूरी भी दे दी गई है। इसमें एक एप्रन भी बनेगा, जहां A-321 तरह के 10 विमान पार्क हो सकेंगे।

2. बिहार के बिहटा में भी एक एयरपोर्ट प्रोजेक्ट शुरू होगा। इसे बनाने के लिए 1413 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई है। इसके बनने से यहां पीक टाइम में तीन हजार यात्री आराम से आ सकेंगे। यहां से सालाना 50 लाख यात्रियों को सुविधा मिलेगी।

ऑल टाइम हाई से फिसला भारत का विदेशी मुद्रा भंडार

नई दिल्ली। एजेंसी

भारत का विदेशी मुद्रा भंडार रिकार्ड ऊंचाई पर पहुंचने के बाद एक बार फिर से फिसल गया है। बीते 9 अगस्त को समाप्त सप्ताह के दौरान भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में $4.80 billion की कमी हुई है। इससे एक सप्ताह पहले इसमें 7.53 अरब डॉलर की भारी बढ़ोतरी हुई थी। इसी के साथ अपना विदेशी मुद्रा भंडार घट कर $670.11 billion पर पहुंच गया है। उधर अपने पड़ोसी देश पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा भंडार तो बढ़ ही रहा है। यह लगातार तीसरा सप्ताह रहा जबकि उसके विदेशी मुद्रा भंडार में बढ़ोतरी हुई है।

कितना रह गया अपना भंडार

भारतीय रिजर्व बैंक (Reserve Bank of India) की तरफ से से जारी आंकड़ों के मुताबिक 9 अगस्त 2024 को समाप्त सप्ताह के दौरान अपना भंडार $4.809 billion घट कर $670.119 billion रह गया है। इससे पहले यानी दो अगस्त 2024 को समाप्त सप्ताह के दौरान इसमें $753 billion की बढ़ोतरी हुई थी और अपना विदेशी मुद्रा भंडार सर्वकालिक उच्चतम स्तर पा पहुंच गया था। रिजर्व बैंक की तरफ से जारी साप्ताहिक आंकड़ों के अनुसार आलोच्य सप्ताह के दौरान भारत की विदेशी मुद्रा आस्तियां (Foreign Currency Asset) में कमी हुई है। बीते 9 अगस्त को समाप्त सप्ताह के दौरान Foreign Currency Assets (FCAs) में $4.079 Billion की कमी हुई है। अब अपना एफसीए भंडार घट कर USD 587.960 Billion रह गया है। उल्लेखनीय है कि कुल विदेशी मुद्रा भंडार में विदेशी मुद्रा आस्तियां या फॉरन करेंसी असेट (FCA) एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। डॉलर में अभिव्यक्त किये जाने वाले विदेशी मुद्रा आस्तियों में यूरो, पौंड और येन जैसे गैर अमेरिकी मुद्राओं में आई घट-बढ़ के प्रभावों को भी शामिल किया जाता है।

गोल्ड रिजर्व भी घटा

बीते सप्ताह देश का गोल्ड रिजर्व भी घट गया है। 9 अगस्त को समाप्त सप्ताह के दौरान भारत के स्वर्ण भंडार (Gold reserves) में 860 Million डॉलर की कमी हुई है। अब अपना सोने का भंडार USD 59.239 Billion का रह गया है।

एसडीआर बढ़ गया

रिजर्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार, बीते सप्ताह भारत के स्पेशल ड्रॉइंग राइट या विशेष आहरण अधिकार (SDR) में बढ़ोतरी हुई है। समीक्षाधीन सप्ताह के दौरान एसडीआर 121 श्ग्त्तदह डॉलर बढ़ कर 18.282 बिलियन डॉलर हो गया है। रिजर्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार, समीक्षाधीन सप्ताह में अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) के पास रखे हुए देश के मुद्रा भंडार में मामूली 18 मिलियन डॉलर के बराबर की बढ़ोतरी हुई है। अब यह बढ़ कर USD 4.638 Billion का हो गया है।

अंबानी ने गड़ाई गैस के कुओं पर नजर!

1000 करोड़ रुपये करेंगे निवेश, जानें क्या है प्लान

नई दिल्ली। एजेंसी

एशिया के सबसे अमीर इंसान और रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी की नजर अब गैस के कुओं पर और गहरी हो गई है। इसके लिए रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (RIL) एक हजार करोड़ रुपये से अधिक का निवेश करेगी। रिलायंस यह निवेश मध्य प्रदेश के सोहागपुर में स्थित अपने कोल बेड मीथेन (CBM) ब्लॉक में करेगी। कंपनी का उद्देश्य इन क्षेत्रों से सीबीएम गैस उत्पादन बढ़ाने का है। बता दें कि सीबीएम कोयले की परतों में इकट्ठी होने वाली प्राकृतिक गैस है। इसे कोयले की परतों में कुओं की ड्रिलिंग करके निकाला जाता है। इसका इस्तेमाल विभिन्न घरेलू और औद्योगिक उद्देश्यों के लिए कंप्रेस्ड नेचुरल गैस (CNG) के रूप में उपयोग किया जाता है।इस मामले में जानकारी रखने वाले एक अधिकारी ने बताया कि रिलायंस इस समय गैस के प्रोडक्शन में गिरावट देख रही है। कंपनी का लक्ष्य अगले

तीन साल में इसके उत्पादन को बढ़ाकर 1 मिलियन स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर (MSCMD) प्रतिदिन करना है। इसके लिए नए कुओं की खुदाई करनी होगी। इसी उद्देश्य से कंपनी इसमें इनकी बड़ी रकम निवेश करना चाहती है। मुकेश अंबानी की कंपनी आरआईएल के मध्य प्रदेश में 995 वर्ग किलोमीटर में फैले दो सीबीएम ब्लॉक हैं।

साल दर साल कम हो रहा गैस का प्रोडक्शन

इन कुओं से अब गैस का प्रोडक्शन साल दर साल कम होता जा रहा है। रिलायंस ने वित्त वर्ष 24 की अपनी वार्षिक रिपोर्ट में कहा है कि यहां से अभी 300 से अधिक कुओं से गैस का प्रोडक्शन हो रहा है। इनसे वर्ष के दौरान औसतन 0.64 एमएससीएमडी गैस का उत्पादन हुआ है। वित्त वर्ष 23 और वित्त वर्ष 22 में इन ब्लॉक से एवरेज प्रोडक्शन 0.73 एमएससीएमडी गैस था। वहीं वित्त वर्ष 21 और वित्त वर्ष 20 में यह 1 एमएससीएमडी था।

कंपनी ने प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए शुरू किया नया प्रोग्राम

रिलायंस के प्रवक्ता ने कहा कि सीबीएम का प्रोडक्शन और भंडार को बढ़ाने के लिए रिलायंस ने मल्टी लेटेरल कुआं (एमएलडब्ल्यू) कार्यक्रम शुरू किया है। प्रवक्ता ने कहा कि पहले 20 कुओं का प्रदर्शन काफी उत्साहजनक रहा है क्योंकि इनसे प्रोडक्शन में काफी बढ़ोतरी हुई है। उन्होंने कहा कि सीबीएम को मार्केटिंग की आजादी है और सरकार द्वारा जारी नीलामी दिशानिर्देशों के अनुसार इसे बेचा जाता है। प्रवक्ता ने कहा कि कंपनी सीबीएम के उत्पादन और भंडार को बढ़ाने के लिए कुओं की खुदाई जारी रखेगी।

कई कंपनियां खरीदती हैं यह गैस

रिलायंस इस गैस को कई कंपनियों को बेचती है। वे कंपनियां इस गैस को जरूरत के अनुसार डिस्ट्रिब्यूट करती हैं। इस साल फरवरी में रिलायंस ने सोहागपुर ब्लॉक से निकलने वाली गैस को बेचने के लिए एक ऑनलाइन नीलामी आयोजित की थी। इसे गेल (इंडिया) और इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड ने खरीदा था।

कम होगा आपके टैक्स का बोझ! 9 सितंबर को मिल सकती है गुड न्यूज

नई दिल्ली। एजेंसी

हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम से उळ्ळ हटाने के मुद्दे पर केंद्र सरकार और विपक्ष की तनातनी के बीच 9 सितंबर को गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स काउंसिल की मीटिंग होने जा रही है। यह काउंसिल की 54वीं मीटिंग होगी। काउंसिल ने पर एक पोस्ट में इसकी जानकारी दी। इस बैठक में जीएसटी दरों में बदलाव और टैक्स स्लैब कम करने पर विचार किया जा सकता है।काउंसिल को पिछली बैठक 23 जून को हुई थी उसके बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा था कि दरों को तर्कसंगत बनाने पर बनाया गया मंत्रियों का समूह अगली बैठक में यह बताएगा कि उसने किन पहलुओं पर गौर किया और इस दिशा में कितना काम हुआ है।

उन्होंने कहा था कि रिपोर्ट तैयार न हुई हो तो मंत्रिसमूह उसका ड्राफ्ट पेश करेगा और काउंसिल रेट रेशनलाइजेशन पर चर्चा शुरू करेगी। 9 सितंबर की बैठक में जीएसटी के तहत ड्यूटी इनवर्जन हटाने पर भी विचार किया जा सकता है।

हेल्थ और मेडिकल इंश्योरेंस

जीएसटी काउंसिल में केंद्रीय वित्त मंत्री के अलावा राज्यों के वित्त मंत्री होते हैं। इसमें एक तिहाई वोटिंग राइट केंद्र का होता हैं और राज्यों के पास दो तिहाई वोटिंग राइट होता है। हेल्थ और मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम पर 18ज्ञ जीएसटी हटाने की विपक्ष की मांग पर वित्त मंत्री ने संसद में कहा था कि यह मसला संसद में नहीं, काउंसिल में उठाया जाना चाहिए और विपक्ष को इसके लिए अपने शासन वाले राज्यों के वित्त मंत्रियों से बात करनी चाहिए।

एक दिन में निकाल दिया 1.34 करोड़ बैरल तेल

जानिए किसने बनाया क्रूड प्रॉडक्शन का रेकॉर्ड

नई दिल्ली। एजेंसी

दुनिया का सबसे बड़ा तेल भंडार वेनेजुएला के पास है। इस दक्षिण अमेरिका देश में दुनिया के ज्ञात क्रूड रिजर्व का 18.2 फीसदी है। उसके बाद सऊदी अरब, कनाडा, ईरान, इराक, कुवैत, यूएई, रूस, लीबिया और नाइजीरिया का नंबर है। ऑयल रिजर्व के मामले में अमेरिका दुनिया में 11वें नंबर पर हैं। उसके पास दुनिया के कुल भंडार का महज 2.1 फीसदी हिस्सा है। लेकिन कच्चे तेल के उत्पादन के मामले में अमेरिका पहले नंबर पर है। अमेरिका में कच्चे तेल का रोजाना उत्पादन 1.34 करोड़ बैरल पहुंच गया है। पिछले साल साल में देश में क्रूड के डेली प्रॉडक्शन में 22 फीसदी तेजी आई है। 2008 से देश का क्रूड प्रॉडक्शन 350% बढ़ चुका है। 16 साल पहले अमेरिका में कच्चे तेल का रोजाना उत्पादन 38 लाख टन था।अमेरिका दुनिया में कच्चे तेल का सबसे बड़ा उत्पादक है। उसका डेली प्रॉडक्शन रूस से 35 फीसदी और सऊदी अरब से 38 फीसदी अधिक है।

अमेरिका ने तेल का उत्पादन बढ़ाकर ओपेक देशों की कटौती को निष्प्रभावी किया है। अमेरिका में कच्चे तेल का उत्पादन करने वाले राज्यों में टेक्सस सबसे आगे है। 2023 में इस प्रांत में दो अरब बैरल से अधिक कच्चे तेल का उत्पादन हुआ। न्यू मैक्सिको तेल उत्पादन में दूसरे नंबर पर है। वहां पिछले साल 66.75 करोड़ बैरल क्रूड प्रॉडक्शन हुआ। सबसे कम क्रूड प्रॉडक्शन वर्जीनिया में है। वहां पिछले साल केवल 5,000 बैरल कच्चे तेल का उत्पादन हुआ। अमेरिका में 50 में से 32 राज्यों में कच्चे तेल का उत्पादन होता है। मई 2023 के आंकड़ों के मुताबिक देश में तेल और गैस के 711 कुएं हैं।

खपत में भी नंबर वन

दुनिया के ऑयल प्रॉडक्शन में पिछले साल अमेरिका की हिस्सेदारी 22% रही। सऊदी अरब 11 फीसदी के साथ दूसरे नंबर पर रहा। इसके बाद रूस, कनाडा, चीन, इराक, ब्राजील, यूएई, ईरान और कुवैत का नंबर है। दुनिया के कुल क्रूड प्रॉडक्शन में इन देशों की 73 फीसदी हिस्सेदारी है। अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक होने के साथ-साथ उपभोक्ता भी है। 2022 में दुनिया के कुल खपत की 20% अमेरिका में रही। चीन दूसरे और भारत तीसरे नंबर पर है।

हवाला और टेरर फंडिंग में क्रिप्टो के लेन-देन का पता लगाता है इंडियन सॉफ्टवेयर

कानपुर। एजेंसी

क्रिप्टो करेंसी का देश और दुनिया में बड़ी संख्या में इस्तेमाल हो रहा है। करोड़ों रुपए के बड़े से बड़े ट्रांजैक्शन चंद सेकंड में क्रिप्टोकरंसी के माध्यम से हो जाते हैं। यह एक ऐसी डिजिटल मनी होती है जिसमें किसी भी प्रकार की केवाईसी की भी जरूरत नहीं होती है। दुनिया भर में आज क्रिप्टो करेंसी इस्तेमाल की जा रही है। क्रिप्टो करेंसी के आने से देश और दुनिया में हवाला और टेरर फंडिंग में भी इसका बड़ी संख्या में इस्तेमाल हो रहा है। देश और दुनिया में कई ऐसे मामले सामने आए हैं जिसमें हवाला और टेरर फंडिंग जैसी एक्टिविटीज में क्रिप्टोकरंसी का इस्तेमाल किया गया है. ऐसे मामलों में पुलिस के सामने आरोपी को पकड़ना सबसे बड़ी चुनौती होती है।

अब इन सब चुनौतियों और क्रिप्टोकरंसी से जुड़े हुए मामलों का पता लगाना आसान होगा क्योंकि आईआईटी कानपुर ने एक ऐसा सॉफ्टवेयर तैयार किया है जो क्रिप्टोकरंसी से जुड़े अपराधों को कैच करने और उनका समाधान निकालने का काम करेगा. इस सॉफ्टवेयर को ब्लॉक स्टेश नाम दिया गया है।

आईआईटी कानपुर के पूर्व छात्र ने किया है तैयार

इस सॉफ्टवेयर को आईआईटी कानपुर के पूर्व छात्र दीपेश चौधरी ने तैयार किया है। वह ब्लॉक स्टेश कंपनी के फाउंडर भी हैं। उन्होंने बताया कि यह सॉफ्टवेयर देश और दुनिया में क्रिप्टोकरंसी से जुड़े मामलों के लिए हर संभव मदद करेगा क्योंकि क्रिप्टोकरंसी से जुड़ा हर एक ट्रांजैक्शन हम लोग इस सॉफ्टवेयर की मदद से ट्रेस कर पा रहे हैं। उन्होंने बताया कि देश और दुनिया में हवाला और टेरर फंडिंग में एक क्रिप्टो वॉलेट से दूसरे क्रिप्टो वॉलेट में पैसा भेजा जाता है जिसके बारे में पता लगाना बेहद कठिन होता है। उन्होंने बताया कि उनके द्वारा तैयार किया गया यह सॉफ्टवेयर जिन खातों में पैसा जाता है जिन जगहों से यह होकर गुजरता है उन सभी का पता लगा लेता है जो पुलिस को आरोपी तक पहुंचने में मदद करती हैं।

दुनिया भर के इंटेलिजेंस कर रहे इस्तेमाल

दीपेश चौधरी ने बताया कि देश के साथ विदेश के भी इंटेलिजेंस और कई राज्यों की पुलिस इस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कर रही है। इस सॉफ्टवेयर की मदद से दुनिया भर के अब तक लगभग 10 से अधिक हाई प्रोफाइल मामलों का खुलासा भी हो चुका है। इसके साथ ही अभी भी देश के कई हाई प्रोफाइल मामलों में इस सॉफ्टवेयर की मदद से काम चालू है. कई बड़ी देश की एजेंसी और इंटेलिजेंस इसका इस्तेमाल कर रही हैं। उन्होंने बताया कि देश के कई हाई प्रोफाइल मामले भी इस सॉफ्टवेयर की मदद से उन लोगों के द्वारा इंटेलिजेंस की टीम के साथ मिलकर खोले गए हैं। कुछ दिन पहले वजीर एए के माध्यम से 2,000 करोड रुपए की राशि भी भारत से किसी दूसरे देश में भेजी गई थी। उसका खुलासा भी इस सॉफ्टवेयर की मदद से हुआ था और इसकी अहम भूमिका इस पूरे केस को सॉल्व करने में रही थी।

अडानी की दक्षिण पर नजर, अंबुजा सीमेंट ने पेन्ना सीमेंट का अधिग्रहण किया पूरा

नई दिल्ली। एजेंसी

अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी ने देश के दक्षिणी हिस्से में अपने कदम बढ़ा दिए हैं। अडानी की कंपनी अंबुजा सीमेंट्स ने पेन्ना सीमेंट इंडस्ट्रीज के साथ अधिग्रहण पूरा कर लिया है। इस अधिग्रहण के साथ ही पेन्ना सीमेंट इंडस्ट्रीज अब अंबुजा सीमेंट्स की पूर्ण स्वामित्व वाली सब्सिडियरी कंपनी बन गई है। बता दें कि अंबुजा सीमेंट्स के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने जून में पेन्ना सीमेंट में 100 फीसदी हिस्सेदारी खरीदने की मंजूरी दी थी। यह सौदा 10422 करोड़ रुपये में हुआ था।

पेन्ना सीमेंट इंडस्ट्रीज साउथ की बड़ी कंपनी है। इस अधिग्रहण के पूरा होने के बाद माना जा रहा है कि अडानी साउथ में भी अपने कारोबार की पकड़ मजबूत करेगी। इस अधिग्रहण के पूरा होने के बाद पूरे भारत के सीमेंट बाजार में अडानी ग्रुप की हिस्सेदारी दो बढ़ गई है। वहीं दक्षिण भारत में हिस्सेदारी में 8 फीसदी का इजाफा हुआ है।

साल 2028 तक 140 MTPA का लक्ष्य

पेन्ना सीमेंट की मौजूदा सीमेंट उत्पादन क्षमता 14 मिलियन टन प्रति वर्ष है। इसमें 10 MTPA पहले से ही ऑपरेशनल है। अडानी सीमेंट साल 2028 तक 140 MTPA क्षमता का लक्ष्य हासिल करना चाहती है। माना जा रहा है कि यह अधिग्रहण इस लक्ष्य को हासिल करने में बड़ा कदम साबित होगा। जानकारों के मुताबिक इस कंपनी के अधिग्रहण से अडानी ग्रुप को न केवल दक्षिण भारत में अपनी उपस्थिति मजबूत करने में मदद मिलेगी, बल्कि वह श्रीलंका के मार्केट में भी प्रवेश कर सकेगा।

पेन्ना सीमेंट की इन राज्यों में है पकड़

पेन्ना सीमेंट के पास आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और राजस्थान (निर्माणाधीन) में 14 मिलियन टन सालाना उत्पादन क्षमता है। इसके अलावा जोधपुर संयंत्र से भी 3 MTPA सीमेंट उत्पादन की क्षमता मिलेगी। अडानी ग्रुप ने अपने एक बयान में कहा था कि यह कोलकाता, गोपालपुर, कराईकल, कोच्चि और कोलंबो में पांच बल्क सीमेंट टर्मिनलों के साथ अडानी समूह के समुद्री परिवहन लॉजिस्टिक्स को भी मजबूत करेगा।

क्या है कंपनी का प्लान?

अडानी ग्रुप काफी तेजी से सीमेंट सेक्टर में अपनी मौजूदगी बढ़ा रहा है। उसकी नजर गुजरात की कंपनी सौराष्ट्र सीमेंट, जयप्रकाश एसोसिएट्स का सीमेंट बिजनेस और एबीजी शिपयार्ड की कंपनी वदराज सीमेंट पर भी है। अडानी ग्रुप का लक्ष्य क्षमता बढ़ाने और अगले तीन से चार वर्षों में आदित्य बिड़ला ग्रुप की अल्ट्राटेक को पछाड़कर देश की सबसे बड़ी सीमेंट कंपनी बनना है। ग्रुप के पास अभी तीन सीमेंट कंपनियां हैं। इनमें अंबुजा, एसीसी और सांघी सीमेंट शामिल हैं। अब पेन्ना सीमेंट भी उसकी झोली में आ चुकी है।

वित्त मंत्री ने कहा- बांग्लादेश संकट के कारण भारत की कपड़ा इंडस्ट्री को नुकसान, जल्द छटेंगे संकट के बादल

नई दिल्ली। एजेंसी

बांग्लादेश में आए संकट का असर भारत की कपड़ा इंडस्ट्री में दिखाई दे रहा है। यह बात वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कही। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश संकट के कारण भारत का कपड़ा उद्योग अनिश्चितता का सामना कर रहा है और इसे नुकसान हो रहा है। वित्त मंत्री ने उम्मीद जताई कि सामान्य स्थिति जल्द ही लौट सकती है। वित्त मंत्री ने ये बातें बजट के बाद भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय बोर्ड को संबोधित करते हुए मीडिया से बातचीत में कहीं। इस दौरान उन्होंने कहा कि पड़ोसी देश के साथ सीमाओं को सुरक्षित रखने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं।

वित्त मंत्री ने भारतीय निवेश के संबंध में कहा कि विशेष रूप से तमिलनाडु के कपड़ा उद्योग ने वहां अच्छे विश्वास से निवेश किया है। यही नहीं, वहां जाकर उन्होंने अच्छा प्रदर्शन भी किया है। उन्होंने कहा कि हमने कम आय वाले देशों के प्रति शुल्क और कोटा के मामले में जो उदार रुख अपनाया है, उसके कारण बांग्लादेश से निर्यात में भी वृद्धि हुई है। वे (बांग्लादेश में स्थित भारतीय परिधान उद्योग) भारत को निर्यात भी कर सकते हैं।

सभी निवेश सुरक्षित

निर्मला सीतारमण ने कहा कि पड़ोसी देश में संकट के कारण परिधान और बुने हुए कपड़े के क्षेत्र में थोड़ी अनिश्चितता देखी जा रही है। उन्होंने कहा कि मुझे उम्मीद है कि सभी निवेश सुरक्षित हैं। मेरे लिए यह देखना अभी जल्दबाजी होगी कि बांग्लादेश में इस स्थिति का हमारी अर्थव्यवस्था पर किस तरह का असर पड़ेगा। मुझे उम्मीद है कि बांग्लादेश की अंतरिम सरकार जल्द से जल्द चीजों को सुलझा लेगी ताकि बांग्लादेश और भारत दोनों के लोग सामान्य स्थिति में वापस आ सकें।पटरी पर लौट रही बांग्लादेश की कपड़ा इंडस्ट्री

इस सप्ताह की शुरुआत में बांग्लादेश में राजनीतिक संकट तब आया जब शेख हसीना ने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया और देश छोड़कर चली गईं। इसके तुरंत बाद संसद को भंग कर दिया गया और अंतरिम सरकार का गठन किया गया। हाल में आई एक खबर के मुताबिक अब बांग्लादेश में स्थिति पटरी पर लौट रही है। कई गारमेंट फैक्ट्री शुरू भी हो गई हैं। बांग्लादेश में जितनी भी गारमेंट फैक्ट्री हैं, उनमें से करीब 25 फीसदी भारतीयों की हैं। इन्होंने वहां जाकर फैक्ट्रियां खोलीं और काफी लोगों को रोजगार दिया। बांग्लादेश की इन फैक्ट्रियों में से करीब 90 फीसदी माल दूसरे देशों में भेजा जाता है।

दुनियाभर में फैला है बिजनेस

बांग्लादेश का कपड़ा कारोबार दुनियाभर में फैला हुआ है। आंकड़ों के मुताबिक बांग्लादेश से हर महीने 3.5 से 3.8 बिलियन डॉलर के बीच का एक्सपोर्ट होता है। इसमें यूरोपियन संघ से लेकर यूके तक शामिल है। वहीं कुल मार्केट का 10 फीसदी हिस्सा अमेरिका में एक्सपोर्ट होता है। अगर भारत की बात करें तो एक्सपोर्ट बांग्लादेश के मुकाबले काफी कम है। यह मात्र 1.3 से 1.5 बिलियन डॉलर के बीच है।

सोने की चमक लौटी, बजट के बाद 5 हजार रुपये तक चढ़े भाव; आगे और तेजी के आसार

नई दिल्ली। एजेंसी

घरेलू बाजार में जुलाई के निचले स्तर से सोना 7 फीसदी से ज्यादा यानी तकरीबन 5 हजार रुपये प्रति 10 ग्राम तक चढ़ चुका है। सोने की कीमतों ने घरेलू बाजार में फिर से रफ्तार पकड़ी है। जुलाई के निचले स्तर से सोना 7 फीसदी से ज्यादा यानी तकरीबन 5 हजार रुपये प्रति 10 ग्राम तक चढ़ चुका है। कीमतों में आगे और भी तेजी के आसार हैं। एमसीएक्स पर सोने का बेंचमार्क अक्टूबर कॉन्ट्रैक्ट मंगलवार 20 अगस्त को 72,272 के ऊपरी स्तर तक चला गया। 25 जुलाई के निचले स्तर से यह 7 फीसदी यानी 7 हजार रुपये प्रति 10 ग्राम ज्यादा है। फिलहाल एमसीएक्स पर सोने की कीमतें 72 हजार रुपये प्रति 10 ग्राम के ऊपर है। इससे पहले केंद्रीय बजट 2024 में इंपोर्ट ड्यूटी में कटौती किए जाने के बाद सोने की कीमतों में 7 हजार रुपये प्रति 10 ग्राम तक की गिरावट देखने को मिली थी। बजट के बाद 25 जुलाई को घरेलू फ्यूचर मार्केट एमसीएक्स (MCX) पर कीमतें गिरकर 67,400 रुपये के निचले स्तर तक चली गई थी। पिछले महीने 23 जुलाई को पेश किए गए आम बजट में सोने पर इंपोर्ट ड्यूटी को 15 फीसदी से घटाकर 6 फीसदी कर दिया गया। इसके अलावा ग्लोबल मार्केट में आई नरमी ने भी घरेलू कीमतों पर दबाव बनाया था।

एमसीएक्स (MCX) पर सोने के बेंचमार्क अगस्त कॉन्ट्रैक्ट ने 18 जुलाई 2024 को रिकॉर्ड बनाया था। उस दिन इंट्राडे ट्रेडिंग में बेंचमार्क अगस्त फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट बढ़कर 74,538 रुपये प्रति 10 ग्राम के न्यू ऑल टाइम हाई पर पहुंच गया था।

ग्लोबल मार्केट में सोने की कीमतों में देखी जा रही रिकॉर्ड तेजी से घरेलू कीमतों को सपोर्ट मिल रहा है। साथ ही अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपये में जारी कमजोरी ने भी सोने की कीमतों को सपोर्ट किया है। ग्लोबल मार्केट में 20 अगस्त को स्पॉट गोल्ड 2,431.60 डॉलर प्रति औंस के ऑल-टाइम हाई पर चला गया। जबकि बेंचमार्क यूएस अक्टूबर कॉन्ट्रैक्ट बढ़कर 2,558 डॉलर प्रति औंस के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया। ग्लोबल लेवल पर गोल्ड इस साल अब तक 22 फीसदी (तकरीबन 500 डॉलर प्रति औंस) से ज्यादा मजबूत हुआ है।

अमेरिका में ब्याज दरों में कटौती की संभावना के फिर से जोर पकड़ने की वजह से फिलहाल गोल्ड में शानदार तेजी देखने को मिल रही है। अमेरिकी डॉलर और बॉन्ड यील्ड में कमजोरी भी कीमतों के लिए एक हद तक मददगार रहा है। यूएस डॉलर इंडेक्स मंगलवार को 7 महीने के अपने निचले स्तर पर चला गया। पिछले 1 महीने में इसमें तकरीबन 3 फीसदी की कमजोरी आई है। समान अवधि के दौरान 10 वर्षीय यूएस बॉन्ड यील्ड में भी तकरीबन 50 बेसिस प्वाइंट की कमी आई है।

इससे पहले अप्रैल और मई में भी सोने की कीमतें कई दफे ऊपरी स्तर तक गई थीं। उस दौरान भी जून में ब्याज दरों में कटौती की संभावना बढ़ गई थी। लेकिन इस संभावना के कमजोर पड़ने के साथ ही मई के आखिरी हफ्ते और जून में कीमतों में करेक्शन देखने को मिला। जून के पहले पखवाड़े में ग्लोबल मार्केट में सोना 2,300 डॉलर से भी नीचे चला गया था। मार्केट में फिलहाल इस बात की संभावना बेहद प्रबल हो गई है कि अमेरिका का केंद्रीय बैंक सितंबर की अपनी बैठक में ब्याज दरों में 25 बेसिस प्वाइंट यानी 0.25 फीसदी की कटौती सकता है। यदि अमेरिका में ब्याज दरों में कमी आती है तो सोने को और सपोर्ट मिलना लाजमी है। सोने पर कोई इंटरेस्ट/ यील्ड नहीं मिलता इसलिए ब्याज दरों के नीचे जाने से निवेश के तौर पर इस एसेट क्लास की पूछ-परख बढ जाती है।

अमेरिका और अन्य विकसित देशों में यदि ब्याज दरें नीचे आती हैं तो शायद गोल्ड में एक स्पष्ट और टिकाऊ तेजी की स्थिति बन सकती है। विकसित देशों के केंद्रीय बैंक यदि इस तरह का कदम उठाते हैं तो पश्चिमी देशों में निवेशकों का रुझान फिर से गोल्ड की तरफ बढ़ सकता है। गोल्ड में पिछले अक्टूबर के बाद से जो शानदार तेजी देखने को मिली है उससे पश्चिमी देशों के रिटेल निवेशक कमोबेश अछूते ही रहे हैं। खासकर ईटीएफ के आंकड़े तो इस बात की तस्दीक करते हैं कि पश्चिमी देशों में रिटेल इन्वेस्टमेंट डिमांड की स्थिति कमजोर बनी हुई है। जानकार मानते हैं कि गोल्ड में आगे जो तेजी होगी उसमें पश्चिमी देशों के निवेशक शायद बड़ी भूमिका निभाएं।

इसके अलावे और भी कई और भी फैक्टर हैं जो गोल्ड को फिलहाल सपोर्ट कर रहे हैं। गोल्ड ईटीएफ में फिर से बढ़ रहा निवेश उन्हीं महत्वपूर्ण फैक्टर में से एक है। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की रिपोर्ट के मुताबिक ग्लोबल लेवल पर लगातार तीसरे महीने जुलाई में गोल्ड ईटीएफ में निवेश में बढ़ोतरी (म्हत्दै) दर्ज की गई। जुलाई 2024 के दौरान ग्लोबल लेवल पर गोल्ड ईटीएफ में निवेश में 3.7 बिलियन डॉलर (48.5 टन सोने की वैल्यू के बराबर) का इजाफा हुआ। जून 2024 के दौरान ग्लोबल लेवल पर गोल्ड ईटीएफ में निवेश में 1.4 बिलियन डॉलर (17.5 टन सोने की वैल्यू के बराबर) का इजाफा हुआ था। इससे पहले लगातार 12 महीने की गिरावट के बाद मई में गोल्ड ईटीएफ में शुद्ध निवेश 0.5 बिलियन डॉलर (8.2 टन सोने की वैल्यू के बराबर) बढ़ा था।

ईटीएफ डिमांड के मामले में चीन और भारत इस साल अभी तक आगे रहे हैं। होलसेल डिमांड के बरक्स चीन में इन्वेस्टमेंट डिमांड में तेजी लगातार आठवें महीने जुलाई के दौरान बरकरार रही। चीन में जुलाई के दौरान गोल्ड ईटीएफ का कुल एसेट अंडर मैनेजमेंट (AUM) 108 मिलियन यूएस डॉलर बढ़कर 7.3 बिलियन डॉलर के रिकॉर्ड हाई पर पहुंच गया। टोटल होल्डिंग्स भी इसी अवधि के दौरान 1.3 टन बढ़कर अब तक के सबसे उच्चतम स्तर 94 टन पर पहुंच गया। इक्विटी में गिरावट के साथ ही सोने की कीमतों में रिकॉर्ड तोड़ तेजी के बीच चीन में गोल्ड ईटीएफ लगातार नई ऊंचाई को छू रहा है।

इस साल जुलाई तक चीन में गोल्ड फंड में 2.5 बिलियन डॉलर का निवेश हुआ है। किसी एक कैलेंडर ईयर के पहले 7 महीनों के दौरान के दौरान चीन के गोल्ड ईटीएफ में यह सबसे ज्यादा निवेश है। पिछले साल की समान अवधि के मुकाबले यह 80 फीसदी ज्यादा है। इसी तरह टोटल होल्डिंग्स में भी इस साल जुलाई तक 32.3 टन का इजाफा हुआ है। पिछले साल की इसी अवधि की तुलना में यह 52 फीसदी ज्यादा है।

ईटीएफ डिमांड भारत में भी रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। सोने की कीमतों में तेजी के रुख के बीच घरेलू स्तर पर गोल्ड ईटीएफ (Gold Exchange Traded Fund) में जुलाई 2024 के दौरान निवेश 1,337 करोड़ रुपये के पार चला गया। फरवरी 2020 के बाद यह सबसे ज्यादा है। गोल्ड ईटीएफ में फरवरी 2020 के दौरान 1,483.33 करोड़ रुपये का शुद्ध निवेश दर्ज किया गया था। इस साल गोल्ड ईटीएफ में अभी तक सिर्फ अप्रैल में निकासी दर्ज की गई जबकि बाकी 6 महीनों के दौरान निवेश में इजाफा देखने को मिला है।

एसोसिएशन ऑफ म्युचुअल फंड्स इन इंडिया (AMFI) के आंकड़ों के अनुसार देश के कुल 17 गोल्ड ETF (Gold Exchange Traded Fund) में जुलाई 2024 के दौरान 1,337.35 करोड़ रुपये का शुद्ध निवेश (inflow) हुआ, जो पिछले साल की समान अवधि के मुकाबले 193 फीसदी ज्यादा है। पिछले साल की समान अवधि के दौरान देश के कुल 13 गोल्ड ईटीएफ में 456.15 करोड़ रुपये का शुद्ध निवेश हुआ था।

जून 2024 के दौरान गोल्ड ईटीएफ में 726.16 करोड़ रुपये का शुद्ध निवेश हुआ था। इस तरह से देखें तो कैलेंडर ईयर 2024 के पहले 7 महीनों (जनवरी- जुलाई) के दौरान गोल्ड ईटीएफ में कुल 4,523.29 करोड़ रुपये का शुद्ध निवेश हुआ। जबकि कैलेंडर ईयर 2023 के पहले 7 महीनों के दौरान 453.55 करोड़ रुपये का शुद्ध निवेश दर्ज किया गया था।

ग्लोबल लेवल पर बढ़ते जियो-पॉलिटिकल टेंशन के बीच निवेश के सुरक्षित विकल्प (safe-haven) के तौर पर भी सोने की मांग बढ़ी है।

हालांकि चीन के केंद्रीय बैंक की तरफ से लगातार तीसरे महीने यानी जुलाई के दौरान सोने की खरीदारी से परहेज करने की वजह से केंद्रीय बैंकों की खरीदारी को लेकर थोड़ी अनिश्चितता बढ़ी है। चीन के गोल्ड रिजर्व की हिस्सेदारी उसके कुल रिजर्व में अभी भी तुलनात्मक रूप से कम है इसलिए कई जानकार मानते हैं कि आने वाले समय में चीन का केंद्रीय बैंक फिर से सोने की खरीदारी शुरू कर सकता है। चीन के कुल फॉरेक्स रिजर्व में फिलहाल गोल्ड रिजर्व की हिस्सेदारी 4.9 फीसदी है। दूसरी तरफ भारत सहित कई देशों के केंद्रीय बैंकों की तरफ से सोने की खरीदारी लगातार जारी है।

वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के हालिया 2024 Central Bank Gold Reserves (CBGR) survey में भी यह बात सामने निकल कर आई है कि 29 फीसदी केंद्रीय बैंक अगले 12 महीने में अपने गोल्ड रिजर्व में बढ़ोतरी करना चाह रहे हैं। इस सर्वे में गोल्ड की खरीदारी को लेकर केंद्रीय बैंकों ने जितना उत्साह जताया है वह वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के इस तरह के बाकी सभी सर्वे के मुकाबले ज्यादा है। पिछले साल के सर्वे में 24 फीसदी केंद्रीय बैंकों ने अपने गोल्ड रिजर्व में वृद्धि करने की इच्छा जताई थी।

हालांकि कीमतों में रिकॉर्ड तेजी के बीच सोने की फिजिकल डिमांड पर असर पड़ सकता है। आंकड़े भी बताते हैं कि चीन में पिछले 3 महीने में फिजिकल डिमांड पर असर पड़ा है। हालांकि इंपोर्ट ड्यूटी में कटौती के बाद भारत में फिजिकल डिमांड में तेजी आई है। लेकिन यदि कीमतें आगे और बढ़ती है तो फिजिकल डिमांड पर इसका असर पड़ सकता है।

गोल्ड बार पहली बार 10 लाख डॉलर के पार, रेकॉर्ड हाई पर पहुंचा सोना, कहां तक जाएगी कीमत

नई दिल्ली। एजेंसी

सोने की कीमत में एक बार फिर भारी तेजी दिख रही है। अमेरिका में पहली बार गोल्ड बार की कीमत 10 लाख डॉलर यानी 8,39,32,800 रुपये के पार पहुंच गई है। मंगलवार को स्पॉट गोल्ड की कीमत 2,500 डॉलर प्रति ट्रॉय आउंस पहुंच गई। सोने के एक औसत बार का वजन 400 ट्रॉय आउंस के बराबर होती है। पिछले एक साल में इसकी कीमत में 32 फीसदी तेजी आई है जबकि इस साल यह 20 फीसदी से अधिक बढ़ चुका है। जानकारों का कहना है कि निवेशक फेड रिजर्व के जल्दी ही ब्याज दरों में कटौती की उम्मीद कर रहे हैं। अमेरिकी डॉलर पर निर्भरता कम करने के लिए दुनियाभर के सेंट्रल बैंक सोने की खरीद कर रहे हैं। इनमें चीन, तुर्की और भारत के सेंट्रल बैंक शामिल हैं।साल की पहली छमाही में दुनिया के सेंट्रल बैंकों ने 483 टन सोना खरीदा। आर्थिक संकट के समय सोने को सबसे सुरक्षित निवेश माना जाता है। इसकी वजह यह है कि जब ब्याज दरों में गिरावट आती है तो सोने की चमक बढ़ जाती है। बॉन्ड्स की तुलना में सोने में निवेश को ज्यादा आकर्षक माना जाता है। निवेशक सोने को महंगाई के खिलाफ हेज के रूप में देखते है। 23 जुलाई को पेश बजट में सोने पर आयात शुल्क में कटौती की घोषणा की गई थी। इसके बाद सोने की कीमत में 6,000 रुपये तक की गिरावट आई थी। एमसीएक्स पर अक्टूबर डिलीवरी वाला गोल्ड आज 96.00 रुपये की तेजी के साथ 71873.00 रुपये प्रति 10 ग्राम के भाव पर ट्रेड कर रहा है।

भारतीय अर्थव्यवस्था के आंकड़े मजबूत

ऊंची विकास दर को बनाए रखने के लिए सुधार की जरूरत

नई दिल्ली। एजेंसी

अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आइएमएफ) की उप प्रबंध निदेशक गीता गोपीनाथ ने कहा है कि भारत की अर्थव्यवस्था के आंकड़े मजबूत हैं और बड़ी मात्रा में सार्वजनिक निवेश को दर्शाते हैं जो विकास को गति देने वाला एक महत्वपूर्ण कारक रहा है। उन्होंने कहा कि भारत को अपनी ऊंची विकास दर को बनाए रखने और पर्याप्त रोजगार सुनिश्चित करने के लिए और सुधार करने चाहिए।

2027 तक भारत के तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का दावा करने वाली गोपीनाथ ने कहा कि यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि आर्थिक विकास के साथ पर्याप्त रोजगार का सृजन हो। दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनमिक्स में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, दीर्घकालिक दृष्टिकोण के लिहाज से राजकोषीय समेकन और विकास के बीच कोई लेनादेना नहीं है, लेकिन अगर किसी देश की राजकोषीय स्थिति ठीक नहीं है तो लंबे समय बाद उसके संकट में फंसने की संभावना अधिक होती है।

इसलिए सरकारें राजकोषीय समेकन ज्यादा ध्यान देती हैं। उन्होंने कहा कि अल्पावधि में राजकोषीय घाटे को कम करने से नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। हालांकि कुछ ऐसे तरीके हैं, जिनसे कोई खास नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ता है। उनके इस बयान को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के उस एलान से जोड़कर देखा जा रहा है, जिसमें उन्होंने 2024-25 के बजट में राजकोषीय घाटे को जीडीपी के 4.9 प्रतिशत तक कम करने की बात कही थी।

राजकोषीय घाटे को कम करने का मुख्य उद्देश्य स्थित विकास को सुनिश्चित करना है, क्योंकि कम राजकोषीय घाटा मुद्रास्फीति को नियंत्रण में रखने में मदद करता है। इससे सरकार द्वारा आवश्यक उधारी भी कम होगी, जिससे बैंकिंग प्रणाली में कंपनियों के लिए कर्ज लेने के लिए अधिक धन बचेगा, जिससे विकास को बढ़ावा मिलेगा और अधिक नौकरियों को सृजन होगा।

अंतरराष्ट्रीय संगठनों के शीर्ष पदों पर महिलाओं की नियुक्ति पर गोपीनाथ ने कहा कि एक समय यह कल्पना भी नहीं की जा सकती थी कि आइएमएफ की प्रबंध निदेशक एक महिला होगी। हालांकि अब हमारे पास एक महिला प्रबंध निदेशक है और पिछली प्रबंध निदेशक भी एक महिला थीं।

इतिहास के विद्यार्थी, आईएएस की परीक्षा क्रैक की, दूसरी बार बने दुनिया के शीर्ष बैंकर

नई दिल्ली। एजेंसी

इतिहास विषय के साथ बीए और एमए की परीक्षा पास की। इसके बाद देश के सबसे कठिन माने जाने वाली यूपीएससी (UPSC) की सिविल सर्विसेज परीक्षा पास कर आईएएस (IAS) बने। अब वह लगातार दो बार दुनिया के शीर्ष बैंकर बने हैं। जी हां, आपने सही समझा। हम रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास की बात कर रहे हैं। वह लगातार दूसरी बार दुनिया के शीर्ष बैंकर बने हैं। उनकी इस उपलब्धि पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बधाई दी है।

क्या उपलब्धि मिली है?

ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन द्वारा पिछले दिनों ही 'सेंट्रल बैंकर रिपोर्ट काड्र्स 2024' में दुनियाभर के केंद्रीय बैंकों के गवर्नर को काम के आधार पर ग्रेड दी थी। उसमें सबसे अच्छी ग्रेड 'S+', 'S' और 'S' हैं। अपने रिजर्व बैंक के गवर्नर को इसमें A+ की ग्रेडिंग मिली है। इसके बाद आरबीआई के सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर एक पोस्ट आया। इसी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास को 'ग्लोबल फाइनेंस सेंट्रल बैंकर रिपोर्ट काड्र्स 2024' में लगातार दूसरी बार 'S+' रेटिंग मिलने पर बधाई दी।

क्या लिखा पीएम मोदी ने

भारतीय रिजर्व बैंक के सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर की गई एक पोस्ट के जवाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिखा कि आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास को लगातार दूसरी बार इस उपलब्धि के लिए बधाई। प्रधानमंत्री ने कहा, 'यह आरबीआई में उनकी लीडरशिप और देश की आर्थिक वृद्धि दर और स्थिरता बनाए रखने के लिए उनके द्वारा किए गए कार्य को प्रमाणित करता है।'

100 देशों के गवर्नर को मिलती है ग्रेडिंग

Global Finance Central Banker Report Cards को 1994 के बाद से हर साल जारी किया जाता है। इसमें करीब 100 देशों के केंद्रीय बैंकों के गवर्नर को काम के आधार पर ग्रेड दी जाती है। इसमें यूरोपियन यूनियन के अलावा पूर्वी कैरेबियाई सेंट्रल बैंक, बैंक ऑफ सेंट्रल अफ्रीकन स्टेट्स और सेंट्रल बैंक ऑफ वेस्ट अफ्रीकन स्टेट्स शामिल हैं। इसमें ग्रेड महंगाई पर नियंत्रण, आर्थिक विकास के लक्ष्य को प्राप्त करने, मुद्रा की स्थिरता और ब्याज दरों के मैनेजमेंट के आधार पर दी जाती है।

महंगाई को काबू करना अहम मुद्दा

ग्लोबल फाइनेंस के संस्थापक और एडिटोरियल डायरेक्टर जोसेफ जियारापुटो ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में केंद्रीय बैंकों ने महंगाई को कम करने के लिए अपने प्राथमिक विकल्प अधिक ब्याज दरों को उपयोग किया है, अब पूरी दुनिया में महंगाई में कमी देखने को मिल रही है। दास ने बीते मंगलवार को ही कहा था कि बैंकों को क्रेडिट और डिपॉजिट में अंतर पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि इससे लिक्विडिटी की समस्या पैदा हो सकती है। एक न्यूज चैनल को दिए इंटरव्यू में आरबीआई गवर्नर ने कहा कि उन्होंने बैंकों को इस स्थिति पर नजर बनाए रखने के लिए कहा है।

इतिहास के विद्यार्थी रहे हैं

शक्तिकांत दास विद्यार्थी जीवन में इतिहास के छात्र रहे हैं। वह दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रतिष्ठित सेंट स्टीफेंस कॉलेज से इतिहास में बीए और इसी विषय में एमए की उपाधि हासिल की है। इसके बाद वह यूपीएससी की सिविल सर्विसेज परीक्षा (Civil Services Exam) को क्रैक कर भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी आईएएस अधिकारी बने।

बदल गया ट्रेंड... लोन से ज्यादा तेजी से बढ़ रहे बैंक डिपॉजिट, आरबीआई डेटा में खुलासा

मुंबई। एजेंसी

चालू वित्त वर्ष के दौरान बैंक क्रेडिट ग्रोथ की रफ्तार धीमी हो रही है जबकि इक्रिमेंटल बैंक डिपॉजिट्स ने एडवांसेज की ग्रोथ को पीछे छोड़ दिया है। आरबीआई के पाक्षिक आंकड़ों के मुताबिक 26 जुलाई, 2024 तक बैंकों में जमा राशि 211.9 लाख करोड़ रुपये थी। बैंकों ने मार्च 2024 से 7.2 लाख करोड़ रुपये की जमा राशि जोड़ी है, जो एक साल पहले की अवधि के दौरान जोड़े गए जमा से 3.5% अधिक है। जुलाई 2024 के अंत में बैंक क्रेडिट 168.1 लाख करोड़ रुपये था। मार्च के अंत से इसमें 3.8 लाख करोड़ रुपये की बढ़ोतरी हुई है। इक्रिमेंटल लोन एक साल पहले की अवधि के दौरान बैंकों द्वारा दिए गए ऋण से 2.3% अधिक है।केयरएज रेटिंग्स के एनालिस्ट्स ने एक रिपोर्ट में कहा कि क्रेडिट ऑफ टेक में कमी जारी है और यह जमा वृद्धि के साथ जुड़ रहा है, जो जमा को बढ़ाने में सिस्टम-वाइड चुनौती को उजागर करता है। पर्सनल लोन ऋण और एमएसएमई में ग्रोथ इस वृद्धि का कारण बनी हुई है। इस बीच क्रमिक रूप से क्रेडिट ग्रोथ स्थिर रही। इसकी वजह यह हो सकती है कि आरबीआई ने असुरक्षित लोन पर लगाम लगाई है। वित्त वर्ष 2025 में डिपॉजिट्स पर जोर रहेगा क्योंकि बैंक अपनी लायबिलिटी फ्रेंचाइज को मजबूत करने के प्रयासों को तेज कर रहे हैं। बैंक सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स के माध्यम से भी धन जुटा रहे हैं।

ऋण-जमा अनुपात

साल-दर-साल प्रदर्शन में क्रेडिट में 13.6% की ग्रोथ देखी गई जो पिछले वर्ष की तुलना में अपेक्षाकृत धीमी थी। पिछले साल इसमें 19.7% की ग्रोथ देखी गई थी जबकि डिपॉजिट में 10.6% की तेजी आई थी। डिपॉजिट ग्रोथ में सुधार तो देखने को मिला है, लेकिन पिछले एक साल में यह क्रेडिट ग्रोथ के मुकाबले पीछे रही है। क्रेडिट में सुस्ती के कारण बैंकों का क्रेडिट-डिपॉजिट रेश्यो लगातार दूसरे पखवाड़े 80% से नीचे रहा है। एचडीएफसी के एचडीएफसी बैंक के साथ मर्जर ने बैंकिंग प्रणाली के लिए ऋण-जमा अनुपात को बढ़ा दिया है। एचडीएफसी द्वारा दिए गए ऋणों को छोड़कर, जमा अनुपात में ऋण 77% के आसपास होगा।

इस रक्षाबंधन टूट गए बिक्री के रेकॉर्ड

Blinkit के फाउंडर ने शेयर किए आंकड़े

नई दिल्ली। आईपीटी नेटवर्क

फेस्टिवल सीजन में ऑनलाइन खरीदारी काफी बढ़ जाती है। रक्षाबंधन से फेस्टिवल सीजन की शुरुआत मानी जाती है। यह सीजन दिवाली के बाद तक रहता है। सीजन की शुरुआत में ही ऑनलाइन बिक्री के पुराने रेकॉर्ड टूट गए हैं। क्विक कॉमर्स कंपनी ब्लिंकिट के फाउंडर अल्बिंदर ढींढसा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट के जरिए बिक्री के कुछ आंकड़े शेयर किए हैं। इन आंकड़ों के मुताबिक ब्लिंकिट ने रक्षा बंधन से ठीक एक दिन पहले रविवार को ऑनलाइन बिक्री का नया रेकॉर्ड बना दिया है।

अल्बिंदर ने यह पोस्ट रविवार रात 9:43 बजे की थी। इसमें उन्होंने लिखा है कि इस बार राखी की बिक्री का भी नया रेकॉर्ड बन गया है। इस पोस्ट को अभी तक करीब एक लाख लोग पढ़ चुके हैं। 900 से ज्यादा यूजर्स इस पोस्ट को लाइक कर चुके हैं और करीब 50 ने रीपोस्ट की है। इसके अलावा 15 से ज्यादा यूजर्स अपनी प्रतिक्रिया भी दे चुके हैं। एक यूजर ने लिखा है कि वह उस दिन का इंतजार कर रहा है जब दवाएं भी 20 मिनट में डिलीवर होंगी।

प्रति मिनट ऑर्डर का बना रिकॉर्ड

अल्बिंदर ने अपनी पोस्ट में लिखा है कि हम कुछ ही मिनटों में एक दिन में सबसे ज्यादा ऑर्डर का रेकॉर्ड तोड़ने वाले हैं। साथ ही उन्होंने लिखा कि प्रति मिनट ऑर्डर का भी नया आंकड़ा छू लिया है। इसके अलावा एक दिन में चॉकलेट और दूसरी चीजें भी बिकने का नया रेकॉर्ड बना है। साथ ही GMV (Gross Merchandise Value) का भी नया रेकॉर्ड बना है। बता दें कि उश्न किसी भी ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर बिक्री से हुई कमाई होती है। यह ऐसी बिक्री होती है जो किसी निश्चित समय में होती है।एक मिनट में बिकीं 693 राखी

ब्लिंकिट ने रविवार को प्रति मिनट राखी बेचने का भी रेकॉर्ड बनाया। अल्बिंदर ने अपनी पोस्ट में लिखा है कि ब्लिंकिट ने प्रति मिनट 693 राखी बेचीं जो एक नया रेकॉर्ड है। उन्होंने अपने सभी ग्राहकों को सर्विस पर भरोसा जताने के लिए धन्यवाद दिया। खासकर उन ग्राहकों को जिन्होंने रविवार को अपना पहला ऑर्डर किया। साथ ही उन्होंने सभी को रक्षा बंधन की भी बधाई दी।

प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, क्या सरकारी बैंकों से लोन लेकर भूल रहे हैं लोग? नीति आयोग की रिपोर्ट

नयी दिल्ली। आईपीटी नेटवर्क

लोगों को स्वरोजगार करनेया लघु उद्योग लगाने के लिए आसानी से लोन मिले, इसके लिए 8 अप्रैल 2015 को प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की शुरुआत की गई थी। लेकिन इसका सदुपयोग कम, दुरुपयोग ज्यादा हो रहा है। इसका इशारा नीति आयोग द्वारा तैयार एक रिपोर्ट से मिलता है। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत दिये जाने वाले लोन की वापसी में लोग ढीले होते जा रहे हैं। तभी तो साल दर साल इस तरह के लोन अकाउंट के एनपीए होने का प्रतिशत बढ़ता जा रहा है।

सरकारी बैंकों के लोन ज्यादा फंस रहे- नीति आयोग की लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक सरकारी बैंकों में पीएमएमवाई के लोन ज्यादा फंस रहे हैं। वहां ऐसे लोन अकाउंट के एनपीए होने की संख्या ज्यादा है। इसके मुताबिक वित्त वर्ष 2017 से 2022 के बीच एनपीए खातों में 22.51 फीसदी चक्रवृद्धि दर से बढ़ोतरी हुई। इस अवधि में एनपीए अकाउंट में फंसी राशि में भी 36.61 फीसदी के सीएजीआर से बढ़ोतरी हुई है। इस रिपोर्ट के मुताबिक सरकारी बैंकों के लोन खाते में जहां 22.6 फीसदी का एनपीए रिकार्ड किया गया वहीं एनबीएफसी में तो यह महज 1.3 फीसदी। यदि एनपीए अकाउंट में फंसी राशि का हिसाब किया जाए तो सरकारी बैंकों में यह 16.9 फीसदी है तो एनबीएफसी में महज 0.5 फीसदी।

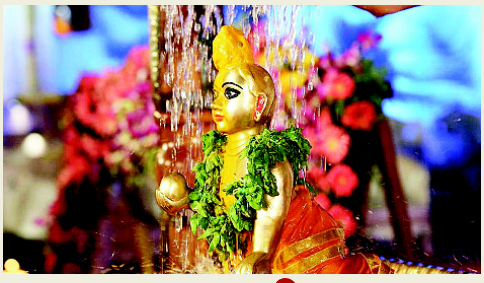

जन्माष्टमी पर पंचामृत से करें बाल गोपाल का अभिषेक

संतान प्राप्ति समेत मिलेंगे कई लाभ

डॉ. आर.डी. आचार्य
9009369396
ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ
इंदौर (म.प्र.)

श्रीकृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर कान्हा की विधि-विधान से पूजा करने के साथ-साथ व्रत भी रखा जाता है। इस दिन बाल गोपाल के जन्मोत्सव के साथ-साथ कुछ विशेष उपाय भी किए जाते हैं।

ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, श्री कृष्ण से जुड़े कुछ खास उपाय जन्माष्टमी के दिन कर लिए जाएं, तो सुख-समृद्धि और धन-संपदा में वृद्धि होती है। साथ ही मां लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। जन्माष्टमी पर बाल गोपाल का पंचामृत से अभिषेक करने से कई तरह के लाभ प्राप्त होते हैं।

जन्माष्टमी 2024 तिथि

भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि 25 अगस्त 2024 रविवार को दोपहर 3 बजकर 39 मिनट पर शुरू होगी। वहीं इसका समापन 26 अगस्त 2024 दिन सोमवार को दोपहर 2 बजकर 19 मिनट पर होगा। ऐसे में जन्माष्टमी 26 अगस्त को मनाई जाएगी।

जन्माष्टमी पर करें ये उपाय

पंचामृत से अभिषेक करें

जन्माष्टमी के अवसर पर भगवान श्रीकृष्ण का पंचामृत से अभिषेक करें। इसके बाद उन्हें लाल वस्त्र पहनाएं। इसके बाद उन्हें झूले में बैठाएं और 27 बार झूला झुलाएं।

गुलाबी वस्त्र अर्पित करें

जन्माष्टमी के खास दिन पर कान्हा को गुलाबी रंग के वस्त्र अर्पित करें। इसके साथ ही थोड़ा सा इत्र भी उन्हें छिड़कें। कहा जाता है कि कान्हा को सुगंधित इत्र बहुत पसंद है। इसके बाद उन्हें 9 बार झूला झुलाएं।

केले का पौधा लगाएं

मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए जन्माष्टमी के मौके पर केले का पौधा लगाएं। इसके साथ ही इसकी नियमित रूप से पूजा-पाठ भी करें। ऐसा करने से आपको भगवान विष्णु का आशीर्वाद भी मिलेगा।

संतान प्राप्ति के लिए उपाय

संतान प्राप्ति के लिए जन्माष्टमी के खास मौके पर कान्हा का पंचामृत से अभिषेक करें। इसके साथ ही उन्हें पीले फूल, माला और वस्त्र अर्पित करें। इसके बाद उन्हें माखन मिश्री का भोग लगाएं। अंत में 'ऊं क्लीं कृष्णाय नमः' मंत्र का जाप करें।

तुलसी की विधिवत पूजा करें

जन्माष्टमी के दिन मां तुलसी की विधिवत पूजा करनी चाहिए। शाम के समय तुलसी के पौधे के पास घी का दीपक भी जलाएं।

सफलता प्राप्त करने के लिए

अगर नौकरी में पदोन्नति चाहते हैं या फिर बिजनेस में अपार सफलता के साथ धन लाभ चाहते हैं, तो जन्माष्टमी के मौके पर भगवान कृष्ण को सफेद चंदन चढ़ाएं। इसके साथ ही गुलाबों से बनी फूल माला चढ़ाएं। उन्हें सफेद रंग के वस्त्र धारण कराने के साथ झूला भी झुलाएं।

तुलसी दल जरूर शामिल करें

भगवान विष्णु को तुलसी अति प्रिय है। ऐसे में भगवान कृष्ण को भोग लगाते समय तुलसी दल जरूर रखें। इससे वह जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं।

कब है जन्माष्टमी... वृषभ राशि में विराजित रहेंगे चंद्रमा, जयंती योग का होगा निर्माण

पं. श्री रमेशचंद व्यास
(चैनपुरा वाले)
ज्योतिषयाचार्य एवं रत्न विशेषज्ञ
मो. 9826345104

जन्माष्टमी में अब कुछ ही दिन शेष बचे हैं। मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु ने श्रीकृष्ण के रूप में धरती पर अवतार लिया था। श्रीकृष्ण का जन्म मथुरा में हुआ था। जबकि, उनका बचपन गोकुल और वृंदावन में बीता था। हिंदू पंचांग के अनुसार, हर साल भादो माह (भाद्रपद मास) के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को जन्माष्टमी पर्व मनाया जाता है। मंदिरों में श्रीकृष्ण की विशेष पूजा की जाती है और रात 12 बजे श्रीकृष्ण जन्म के समय पर मंदिरों में विशेष आरती की जाती है। यहां आपको बताते हैं, इस बार जन्माष्टमी कब मनाई जाएगी और इसका शुभ मुहूर्त क्या है।

जन्माष्टमी 2024 तिथि और शुभ मुहूर्त

हिंदू पंचांग की मानें तो इस बार 26 अगस्त (सोमवार) को मनाया जाएगा। सुबह 3 बजकर 40 मिनट से अष्टमी तिथि शुरू होगी और अगले दिन यानी 27 अगस्त को सुबह 2 बजकर 19 मिनट पर इसका समापन होगा। पूजा का शुभ समय मध्य रात्रि 12:02 से रात्रि 12:45 तक रहेगा। व्रत का पारण 27 अगस्त को सुबह 6:36 तक किया जा सकता है। ज्योतिषियों के अनुसार, इस साल जन्माष्टमी पर चंद्रमा, वृषभ राशि में विराजित रहेंगे, जिससे जयंती योग का निर्माण होगा। इस योग में पूजा करना बहुत शुभ माना जाता है।

जन्माष्टमी 2024 पर व्रत का महत्व

ब्रह्मवैवर्त पुराण के अनुसार, श्री कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत काफी शुभ फलदायी होता है। इससे 100 जन्मों के पापों से मुक्ति मिलती है। साथ ही व्रती को बैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है और वह उत्तम योनि में जन्म लेता है।

इन नियमों का करें पालन

जन्माष्टमी व्रत करना शुभ फलदायी माना गया है। हालांकि, इस दिन कई नियमों का पालन जरूरी होता है।

जन्माष्टमी व्रत के दिन अन्न ग्रहण न करें।

व्रत का पारण अष्टमी तिथि के बाद करें।

वत में मन में कोई गलत विचार न लाएं।

मांस, मदिरा के सेवन से दूर रहना चाहिए।

कान्हा को प्रिय हैं ये रंग, जन्माष्टमी पर पहनें इस रंग के वस्त्र, कृष्ण होंगे प्रसन्न

श्रीकृष्ण का रंग, रूप बेहद ही मनमोहक था, श्यामवर्ण वाले कान्हा की एक झलक पाने के लिए गोपियां कई तरह के जतन करती थी. श्रीकृष्ण को कुछ खास रंग बेहद प्रिय थे, कहते हैं कि कृष्ण जन्माष्टमी पर उन रंग के कपड़े पहनने से बाल गोपल की कृपा बरसती है.

श्रीकृष्ण को गुलाबी, लाल, पीला, मोरपंखी रंग बेहद प्रिय है. 26 अगस्त को जन्माष्टमी पर इस रंग के वस्त्र धारण करना शुभ होता है. मान्यता है कि मां यशोदा भी

कान्हा को ज्यादातर इन्हीं रंगों के कपड़े पहनाती थीं.

बाल गोपाल को गोपी चंदन बेहद प्रिय है, जन्माष्टमी पर पूजा में तो इसका इस्तेमाल करें साथ ही स्वंय भी गोपिका चंदन से तिलक करें. इससे मानसिक तनाव दूर होता है. जन्माष्टमी के दिन रातरानी के फूलों का इत्र लगाना अच्छा माना जाता है. कहते हैं श्रीकृष्ण के शरीर से भी मादक गंध आती थी. ग्रंथों के अनुसार कान्हा के शरीर से अष्टगंध की सुगंध आती थी. इस खुशबू से वह जल्द प्रसन्न होते हैं.

जन्माष्टमी के अवसर पर कान्हा जी को बांसुरी प्रिय है. वास्तु शास्त्र के अनुसार, घर में बांसुरी रखने से सुख और समृद्धि का आगमन होता है.

पंडित कपिल पाराशर
ज्योतिष आचार्य
वास्तु विशेषज्ञ
6261493070

कृष्ण जन्माष्टमी 26 अगस्त 2024 को मनाई जाएगी. इस दिन कान्हा को उनकी प्रिय वस्तु अर्पित करने से व्यक्ति की समस्याओं का अंत होता है.

पं. राजेश वैष्णव
शनि उपासक ज्योतिष रत्न एवं वास्तु विशेषज्ञ
98272 88490

शनि देव को अगर जान लेंगे तो कभी नहीं कहेंगे ये खराब फल देते हैं

शनि देव को ज्योतिष ग्रंथों में सबसे पावरफुल ग्रहों में से एक माना गया है. शनि ग्रह को लेकर ज्यादातर लोगों में ये धारणा है कि ये खराब ही करते हैं. जबकि ऐसा कतई नहीं है. किसी भी ग्रह के बारे में गलत राय नहीं बनानी चाहिए. ऐसा करने से भी ग्रहों की शुभता अशुभता में बदल जाती है. शनि महाराज शुभ हैं या अशुभ, समझते हैं.

शनि कौन हैं

पद्म पुराण और ब्रह्मवैवर्त पुराण में भी शनि के बारे में वर्णन मिलता है. एक पौराणिक कथा के अनुसार एक बार धन की देवी लक्ष्मी ने शनि देव से प्रश्न किया- 'हे! शनि देव आप सभी लोगों की धन की हानि करते हैं, क्यों सभी आपकी दृष्टि से पीड़ित रहते हैं.' शनि देव ने उत्तर दिया-'माता इसमे मेरा कोई दोष नहीं है, भगवान शिव ने उन्हें तीनों लोक का न्यायाधीश बनाया है, इसलिए जो भी गलत और अनैतिक कार्य करता है, उसे दंड देना ही पड़ता है.'

शनि से किन लोगों को नहीं घबराना चाहिए

शनि की क्रूर दृष्टि से बचना है तो उन कामों को कभी नहीं करना चाहिए जो गलत हैं. जो लोग नियमों का पालन नहीं करते हैं. दूसरों को सताते हैं, उनका धन, भूमि, मान-सम्मान छीनने का प्रयास करते हैं उन्हें शनि किसी भी कीमत पर माफ नहीं करते हैं. समय आने पर शनि देव इन गलत कामों की सजा देकर ही रहते हैं.

शनि को शांत रखने के लिए क्या करें

शनि को झूठ बोलने वाले और

दिखावा करने वाले लोग पसंद नहीं हैं, इसलिए इनसे बचना चाहिए. शनि जीवन में शुभ फल दें और किसी प्रकार का अनिष्ठ न करें इसके लिए कमोजर लोगों की मदद करें, उनके कल्याण के लिए कार्य करें. जो लोग मेहनत-मजदूरी कर अपना और अपने परिवार का पेट भरते हैं, उन्हे किसी भी स्थिति में न सताएं. ऐसा करने पर शनि भयंकर परिणाम देते हैं, यहां तक की ऐसे पाप की सजा आने वाली संतानों को भी झेलनी पड़ती हैं.

इसलिए जहां तक संभव हो इनसे मीठा बोलें, इनकी सहायता करें. उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करें. यदि ऐसा करते हैं तो शनि आपको निश्चित ही शुभ फल प्रदान करेंगे और जीवन में बड़ी सफलताएं दिलाएंगे.

ऑल्टो, ब्रेजा, वैगनआर... सस्ती हो सकती हैं मारुति की गाड़ियां, जानिए क्या है वजह

नई दिल्ली। एजेंसी

देश की सबसे बड़ी ऑटो कंपनी मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड की गाड़ियां आने वाले दिनों में सस्ती हो सकती हैं। 2024-25 की पहली तिमाही में कंपनी के प्रॉडक्शन में पिछले साल के मुकाबले 7.4 फीसदी तेजी रही। इस दौरान कंपनी ने 496,000 गाड़ियां बनाई। लेकिन दौरान कंपनी की बिक्री में केवल 1.2 फीसदी तेजी आई। अप्रैल-जून तिमाही में कंपनी ने 427,000 गाड़ियां बेची। यानी डीलर के पास अभी अच्छी-खासी इंवेंट्री पड़ी है। कंपनी का कहना है कि साल की पहली तिमाही में भारतीय बाजार में यात्री गाड़ियों की मांग उम्मीद से कम रही। इसलिए वह अपने प्रॉडक्शन को एडजस्ट कर रही है ताकि डीलर इंवेंट्री को कम किया जा सके।मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कंपनी में मैज्योरिटी शेयरहोल्डर सुजुकी मोटर कॉरपोरेशन ने एक कॉन्फ्रेंस कॉल में कहा कि मार्केट स्टॉक को कम करने के लिए कंपनी अपने प्रॉडक्शन को एडजस्ट कर रही है। साथ ही कंपनी

की नजर डिमांड ट्रेंड्स पर भी है। फेस्टिव सीजन हमारे लिए अहम है और कंपनी डिमांड ट्रेंड्स पर करीबी नजर रखेगी। डिमांड घटने से डीलरों के पास इंवेंट्री बहुत बढ़ गई है। फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन (FADA) ने इस बारे में सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल एसोसिएशन (SIAM) को हाल के महीनों में दो पत्र लिखकर डीलर्स के पास इंवेंट्री बढ़ने की बात कही है।

दो महीने के बराबर इंवेंट्री

FADA का कहना है कि उसके मेंबर्स डीलरों के पास करीब 730,000 गाड़ियों की इंवेंट्री है जो दो महीने की बिक्री के बराबर है। हालांकि एसोसिएशन का दावा है कि यह संख्या 400,000 यूनिट के करीब है। सुजुकी मोटर कॉरपोरेशन ने एनालिस्ट्स से कहा कि अमूमन भारतीय बाजार में पहली तिमाही में डिमांड कम रहती है लेकिन इस बार डिमांड उम्मीद से कम रही। आम चुनावों, भारी बारिश और लू इसका कारण हो सकता है। इंवेंट्री बढ़ने से कंपनी एडजस्टमेंट कर रही है। इस साल फेस्टिवल सीजन पिछले साल के मुकाबले जल्दी शुरू हो रहा है। डिमांड बढ़ने से फेस्टिव सीजन में अच्छी बिक्री हो सकती है।

देश में खूब उड़ रहे लोग!

जुलाई में 1.30 करोड़ लोगों ने किया सफर

जानें किस एयरलाइन कंपनी ने बनाया दबदबा

नई दिल्ली। एजेंसी

देश में घरेलू हवाई यात्रा करने वालों की संख्या पिछले साल के मुकाबले बढ़ गई है। आंकड़ों के मुताबिक जुलाई में 1.29 करोड़ से ज्यादा लोगों ने घरेलू हवाई यात्रा की। यह आंकड़ा पिछले साल की समान अवधि के मुकाबले 7.3 फीसदी ज्यादा है। ये आंकड़े नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) ने सोमवार को जारी किए। हालांकि आंकड़ों के मुताबिक जुलाई में डोमेस्टिक ट्रैवल करने वालों की संख्या जून के मुकाबले कम रही। जून में 1.32 करोड़ लोगों ने डोमेस्टिक फ्लाइट के जरिए सफर किया था। DGCA के मुताबिक इंडिगो ने घरेलू हवाई यातायात पर अपना दबदबा बनाए रखा। जुलाई में इस एयरलाइन की मार्केट में हिस्सेदारी बढ़कर 62 फीसदी हो गई। वहीं एयर इंडिया की हिस्सेदारी घटकर 14.3 फीसदी रह गई। विस्तारा की घरेलू बाजार हिस्सेदारी 10 फीसदी बढ़ गई। दूसरी ओर एयर इंडिया कनेक्ट की हिस्सेदारी घटकर 4.5 फीसदी और स्पाइसजेट की हिस्सेदारी घटकर 3.1 फीसदी रह गई। इसके अलावा अकासा एयर और एलायंस एयर की हिस्सेदारी भी घटकर क्रमशः 4.7 फीसदी और 0.9 फीसदी रह गई।

7 महीने में 9 लाख से ज्यादा ने किया सफर

डीजीसीए ने कहा कि इस साल जनवरी से जुलाई के बीच इन 7 महीनों में घरेलू एयरलाइनों में यात्रियों की संख्या 923.35 लाख रही। वहीं पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान यह संख्या 881.94 लाख थी। इस प्रकार वार्षिक वृद्धि 4.70 फीसदी और मासिक वृद्धि 7.33 फीसदी रही।

मुआवजे के तौर पर खर्च करनी पड़ी बड़ी रकम

आंकड़ों से यह भी पता चला कि 1114 यात्रियों को विमान में चढ़ने से मना कर दिया गया और एयरलाइंस ने मुआवजे और सुविधाओं के लिए 112.71 लाख रुपये खर्च किए। वहीं कैंसिलेशन से 1,54,770 यात्री प्रभावित हुए और एयरलाइनों ने इस संबंध में मुआवजे और सुविधाओं के लिए 110.59 लाख रुपये खर्च किए। जुलाई में उड़ानों में देरी के कारण 3,20,302 यात्री प्रभावित हुए और एयरलाइनों ने सुविधा के लिए 341.05 लाख रुपये खर्च किए।

1097 शिकायतें मिलीं

जुलाई में एयरलाइनों का कैंसिलेशन रेट 1.90 फीसदी तक पहुंच गया। डीजीसीए ने कहा कि जुलाई 2024 के दौरान घरेलू एयरलाइनों को कुल 1097 शिकायतें मिलीं। जुलाई 2024 में प्रति 10 हजार यात्रियों पर शिकायतों की संख्या करीब 0.84 रही।

अडानी के लिए खुशखबरी!

जिस प्लांट से सिर्फ बांग्लादेश को होनी थी सप्लाई, अब उसी से भारत में बेची जाएगी बिजली

नई दिल्ली। एजेंसी

अडानी पावर ने बांग्लादेश को बिजली सप्लाई के लिए नए कोयला आधारित बिजली संयंत्र की शुरुआत की है। यह प्लांट झारखंड के गोड्डा में है। इसकी क्षमता 1,600 मेगावाट (MW) है। पहले यह संयंत्र सिर्फ बांग्लादेश को ही बिजली निर्यात कर सकता था। लेकिन, अब केंद्र सरकार ने बिजली निर्यात नियमों में बदलाव किया है। इससे गौतम अडानी के नेतृत्व वाली अडानी पावर अब इस संयंत्र से भारत में भी बिजली बेच सकेगी। रायटर्स की रिपोर्ट के अनुसार, यह बदलाव 12 अगस्त को जारी एक इंटरनल मेमो (आंतरिक ज्ञापन) के जरिये किया गया। यह ज्ञापन 2018 के उन दिशानिर्देशों में संशोधन करता है जो विशेष रूप से पड़ोसी देश को बिजली आपूर्ति करने वाले बिजली उत्पादकों पर लागू होते हैं।

अडानी ग्रुप को क्या मिलेगी सहूलियत?

सरकार के ज्ञापन में कहा गया है, 'भारत सरकार ऐसे उत्पादन स्टेशन को भारतीय ग्रिड से जोड़ने की अनुमति दे सकती है। ऐसा पूरी या आंशिक क्षमता के निरंतर गैर-निर्धारण के मामले में भारत के भीतर बिजली की बिक्री की सुविधा के लिए किया जा सकता है।' यह संशोधन अडानी ग्रुप को भुगतान में देरी होने पर स्थानीय ग्रिड को बिजली बेचने की भी इजाजत देता है।

बांग्लादेश में राजनीतिक अस्थिरता

यह बदलाव ऐसे समय में हुआ है जब पड़ोसी देश राजनीतिक अस्थिरता से जूझ रहा है। हाल ही में हुए हिंसक विरोध प्रदर्शनों के बाद शेख हसीना को देश छोड़कर भारत में शरण लेनी पड़ी है। अडानी ग्रुप के एक प्रवक्ता ने मंगलवार को कहा कि इस कदम से देशभर में बढ़ती बिजली की मांग को पूरा करने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा, 'अडानी पावर बांग्लादेश पावर डेवलपमेंट बोर्ड के डिमांड शेड्यूल और बिजली खरीद समझौते के प्रावधानों के अनुसार अनुबंध संबंधी दायित्वों को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है और पारस्परिक पूर्ति जारी रखने के लिए तत्पर है।'

रूस में इस खास बिजनेस के जबरदस्त मौके, निवेश और एक्सपोर्ट पर फोकस- 26 अगस्त को रवाना होगा प्रतिनिधिमंडल

नई दिल्ली। एजेंसी

लेदर के कपड़े, सामान और जूते जैसे सेक्टरों में एक्सपोर्ट के बड़े मौके हैं। हालांकि, रूस-यूक्रेन युद्ध की वजह से पश्चिमी देशों के प्रतिबंधों से रूस में पेमेंट संबंधी समस्याएं हैं, लेकिन रुपये में कारोबार करने वाले एक्सपोर्टर माल भेज सकते हैं। लेदर सेक्टर के 20 से ज्यादा अधिकारियों का एक प्रतिनिधिमंडल इस महीने रूस की यात्रा करेगा। इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य इंवेस्टमेंट की तलाश करना और बढ़ते एक्सपोर्ट के मौकों का लाभ उठाना है। 3 दिनों की ये यात्रा 26 अगस्त को शुरू होगी। लेदर एक्सपोर्ट काउंसिल के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर आर. सेल्वम ने बताया कि वर्तमान में भारत 6-8 करोड़ डॉलर की चमड़े की चीजों का निर्यात करता है, लेकिन ये अभी भी कम है क्योंकि रूस में जबरदस्त मौके हैं। सेल्वम ने कहा, ''हम मॉस्को में आयोजित होने वाले अंतरराष्ट्रीय मेले यूरो शूज प्रीमियर कलेक्शन में भी हिस्सा लेंगे। हम निवेश आकर्षित करने, उत्पाद निर्माण में टेक्नोलॉजी की मदद के उद्देश्य से एक प्रतिनिधिमंडल ले जा रहे हैं।''

चालू वित्त वर्ष में घटकर 1.421 करोड़ डॉलर हुआ निर्यात

आर. सेल्वम ने कहा कि लेदर के कपड़े, सामान और जूते जैसे सेक्टरों में एक्सपोर्ट के बड़े मौके हैं। हालांकि, रूस-यूक्रेन युद्ध की वजह से पश्चिमी देशों के प्रतिबंधों से रूस में पेमेंट संबंधी समस्याएं हैं, लेकिन रुपये में कारोबार करने वाले एक्सपोर्टर माल भेज सकते हैं। लेदर, लेदर के सामानों और जूते का निर्यात 2022-23 में 4.484 करोड़ डॉलर से बढ़कर 2023-24 में 6.248 करोड़ डॉलर हो गया। हालांकि, चालू वित्त वर्ष 2024-25 में अप्रैल-जून के दौरान निर्यात घटकर 1.421 करोड़ डॉलर रह गया, जबकि पिछले साल इसी अवधि में ये 1.634 करोड़ डॉलर था। उन्होंने कहा, ''इस गिरावट का मुख्य कारण पेमेंट की समस्या है, जो बैंकों द्वारा बीआरसी (बैंक प्राप्ति प्रमाणपत्र) जारी न करने के कारण है।''

लोकल करेंसी में बिजनेस करने पर चर्चा कर रहे हैं भारत और रूस

लेदर एक्सपोर्ट काउंसिल के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर आर. सेल्वम ने कहा कि अमेरिकी ओएफएसी (विदेशी संपत्ति नियंत्रण कार्यालय) द्वारा रूस के एसईबीआर बैंक पर प्रतिबंध लगाए गए हैं। प्रतिबंधों के कारण कई भारतीय बैंक रूस से पेमेंट के लिए बीआरसी जारी नहीं कर रहे हैं। भारत और रूस द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देने के लिए लोकल करेंसी में बिजनेस करने और रूस द्वारा गैर-शुल्क बाधाओं को कम करने पर चर्चा कर रहे हैं। भारत और रूस ने 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को 100 अरब अमेरिकी डॉलर तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा है।

रिलायंस पावर के अच्छे दिन, लगातार तीसरे दिन अपर सर्किट में फंसा शेयर

52 हफ्ते के टॉप पर कीमत

नई दिल्ली। एजेंसी

भारी कर्ज में डूबे उद्योगपति अनिल अंबानी के लिए लंबे समय बाद गुड न्यूज आई है। उनकी कंपनी रिलायंस पावर के शेयरों में पिछले तीन दिन से अपर सर्किट लग रहा है। बुधवार को कंपनी का शेयर 5₹ तेजी के साथ 36.17 रुपये पर पहुंच गया जो इसका 52 हफ्ते का उच्चतम स्तर है। पिछले तीन दिन में इसके शेयरों में 15₹ तेजी आई है। हाल में खबर आई थी कि गौतम अडानी की कंपनी अडानी पावर ने नागपुर में एक थर्मल पावर प्रोजेक्ट को खरीदने के लिए बातचीत शुरू की है। यह प्लांट विदर्भ पावर इंडस्ट्रीज का हिस्सा है जो रिलायंस पावर की सब्सिडियरी है। इसके बाद से रिलायंस पावर के शेयरों में भारी तेजी दिख रही है।इस तेजी के साथ ही रिलायंस पावर का मार्केट कैप

14,529.38 करोड़ रुपये पहुंच गया है। रिलायंस पावर का आईपीओ जनवरी 2008 में आया था। इसका साइज 11,563 करोड़ रुपये का था। इसका इश्यू प्राइस 405–450 रुपये था। इसे निवेशकों ने हाथोंहाथ लिया था। इसे 70 गुना बोलियां मिली थी। लिस्टिंग के दिन यह 21₹ प्रीमियम के साथ 547.80 रुपये पर पहुंच गया था। लेकिन इसके बाद इसने निवेशकों को निराश किया। 27 मार्च, 2020 को इसकी कीमत 1.13 रुपये रह गई थी। हालांकि पिछले चार साल में इसमें काफी तेजी आई है। पिछले एक साल में इसकी कीमत में 115 फीसदी तेजी आई है।

मुकेश अंबानी वर्सेज अनिल अंबानी

भारत और एशिया के सबसे बड़े रईस मुकेश अंबानी के छोटे भाई अनिल अंबानी की गिनती कभी देश के टॉप रईसों में होती थी। फोर्ब्स इंडिया की 2007 में प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार अनिल अंबानी की नेटवर्थ 45 अरब डॉलर थी। उस समय वह देश के तीसरे बड़े रईस थे। लेकिन आज उनकी नेटवर्थ जीरो है। मुकेश अंबानी 113 अरब डॉलर की नेटवर्थ के साथ दुनिया के अमीरों की लिस्ट में 11वें नंबर पर हैं। इस साल उनकी नेटवर्थ में 16.4 अरब डॉलर की तेजी आई है।

केडीएम ने शुरू किया अपना इंडिपेंडेंस डे कैंपेन केडीएम भारत का चार्जर

इंदौर। आईपीटी नेटवर्क

भारत के एक बड़े लाइफस्टाइल और मोबाइल एक्सेसरीज ब्रांड केडीएम ने अपना इंडिपेंडेंस डे कैंपेन केडीएम भारत का चार्जर को शुरू कर दिया है जो केडीएम मोबाइल फोन चार्जर से मोबाइल फोन को चार्ज चार्ज करने का ध्यान रखते हुए देश की प्रगति को दर्शाता है आज मोबाइल फोन प्रगति का उपकरण है जिसका देश की आर्थिक हालत में योगदान होता है और कोई भी केडीएम चार्जर की तरह मोबाइल को चार्ज नहीं करता है इसलिए केडीएम सही मायने में भारत का चार्जर है जो आपके मोबाइल और अर्थव्यवस्था दोनों को चार्ज करता है। केडीएम के संस्थापक एन डी माली ने कहा भारत 2047 तक विकसित भारत की अपनी यात्रा पर आगे बढ़ रहा है, मेक इन इंडिया के साथ-साथ हमें मेक फॉर द वर्ल्ड के मंत्र के साथ भी आगे बढ़ना चाहिए। केडीएम के सह-संस्थापक बी एच सुथार ने कहा भारत अपनी आज़ादी का जश्न मनाते हुए गर्व कर रहा है हम हर घर केडीएम के अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए भी तैयार हैं हम केडीएम चार्जर के साथ-साथ केडीएम के प्रोडक्ट्स की बेहतरीन रेंज के साथ भारत के हर घर तक पहुँचना चाहते हैं। इसके अलावा, हम देश की आर्थिक विकास में योगदान देना चाहते हैं और अपने चार्जर्स के साथ भारत को एक मज़बूत देश बनाना चाहते हैं। ये चार्जर डिस्ट्रीब्यूटरों, डीलरों और रिटेलरों के ज़रिए पूरे भारत में अपने पार्टनर स्टोरों पर उपलब्ध हैं।

ओला इलेक्ट्रिक ने बाजार में अपनी स्थिति मजबूत की

इलेक्ट्रिक मोटरसाईकल लॉन्च की एवं वित्तवर्ष 2026 की पहली तिमाही तक अपने खुद के सेल लाने की घोषणा की

इंदौर। आईपीटी नेटवर्क

भारत को विश्व का इलेक्ट्रिक वाहन और नया ऊर्जा केंद्र बनाने के उद्देश्य से ओला इलेक्ट्रिक ने आज इलेक्ट्रिक वाहन और एनर्जी वर्टिकल्स में अपने नए उत्पादों और भविष्य के रोडमैप की घोषणा की रोडस्टर रोडस्टर एक्स और रोडस्टर प्रो के लॉन्च के साथ कंपनी ने आज इलेक्ट्रिक मोटरसाईकल के सेगमेंट में प्रवेश किया और वित्तवर्ष2026 की पहली तिमाही से अपने वाहनों में अपने खुद के सेल लाने की घोषणा की कंपनी ने 15अगस्त 2024 को कृष्णागिरी तमिल नाडु की फ्यूचर फैक्ट्री में ओला की वार्षिक लॉन्च इवेंट संकल्प 2024 में स्वदेशी विकसित भारत 4680सेल और बैटरी पैक तथा मूवओएस 5 का प्रदर्शन भी किया। इस कार्यक्रम में ओला इलेक्ट्रिक के फाउंडर एवं सीएमडी, भाविश अग्रवाल ने कहा आज भारत में टूव्हीलर के दो तिहाई हिस्से पर मोटरसाईकल का कब्जा है और इस सेगमेंट में ओला के प्रवेश के साथ भारत के टूव्हीलर उद्योग में इलेक्ट्रिक वाहनों का हिस्सा तेजी से बढ़ेगा हमने स्कूटर सेगमेंट में इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद में सफलतापूर्वक तेजी लाई, और अब अपने भविष्य के मोटरसाईकल पोर्टफोलियो के साथ हम इलेक्ट्रिक वाहन को और ज्यादा बढ़ावा देने के लिए बहुत उत्साहित हैं। अगले साल की शुरुआत में हमारे वाहनों में हमारे खुद के सेल लगना शुरू हो जाने के बाद हमें विश्वास है कि भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों का बहुत तेजी से विस्तार होगा।

टाटा मोटर्स ने 250 फास्ट-चार्जिंग स्टेशन लगाने के लिये

डेल्टा इलेक्ट्रॉनिक्स और थंडरप्लस सॉल्यूशंस के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किये

मुंबई। आईपीटी नेटवर्क

भारत में वाणिज्यिक वाहन बनाने वाली सबसे बड़ी कंपनी, टाटा मोटर्स ने आज डेल्टा इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया और थंडरप्लस सॉल्यूशंस प्रा. लि. के साथ साझेदारी करने की घोषणा की है। यह साझेदारी टाटा मोटर्स के इलेक्ट्रिक वाणिज्यिक वाहनों के लिए चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार करने के लिये की गई है और इसके तहत देशभर में 250 नये फास्ट चार्जिंग स्टेशन स्थापित किये जाएंगे। यह नये चार्जिंग स्टेशन दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, बेंगलुरु, पुणे और कोच्चि, आदि समेत 50 से ज्यादा शहरों में और उनके आस-पास रणनीतिक रूप से स्थित होंगे। यह 540 कमर्शियल व्हीकल चार्जिंग पॉइंट्स के मौजूदा नेटवर्क में उल्लेखनीय विस्तार करेंगे।

ई-कॉमर्स कंपनियाँ, पार्सल और कुरियर सेवा प्रदाता तथा अन्य उद्योग लास्ट-माइल डिलीवरीज में अपना कार्बन फुटप्रिंट कम करने के लिये कमर्शियल इलेक्ट्रिक वाहनों को तेजी से अपना रहे हैं। कमर्शियल इलेक्ट्रिक गाडियों में आ रहे बदलाव को समझते हुए, टाटा मोटर्स इन फास्ट-चार्जिंग स्टेशनों की स्थापना के लिये सही जगहें और नजदीकी डीलरशिप बताएगी। इधर डेल्टा इलेक्ट्रॉनिक्स जरूरी हार्डवेयर की आपूर्ति करेगी, जबकि थंडरप्लस सॉल्यूशंस उनकी स्थापना एवं परिचालन करेगी।

इस गठजोड़ के बारे में श्री विनय पाठक, वाइस प्रेसिडेंट एण्ड बिजनेस हेड- एससीवी एण्ड पीयू, टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल्स ने कहा, "हम उत्सर्जन से मुक्त कार्गो परिवहन को सबकी पहुंच में लाना चाहते हैं। ज्यादा इस्तेमाल वाले मार्गों पर उपलब्ध चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार करने से अधिक ग्राहकों को इलेक्ट्रिक कमर्शियल व्हीकल्स अपनाने का प्रोत्साहन मिलेगा।

मच्छर के 'डंक' से परेशान हैं हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियां, जानें क्या है वजह

नई दिल्ली। एजेंसी

मच्छरों का डंक हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियों पर भारी पड़ रहा है। बीमा कंपनियों को मिले हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम्स में से लगभग एक तिहाई की वजह मौसमी संक्रामक बीमारियां है। इनमें मच्छर की वजह से फैलने वाली डेंगू और मलेरिया जैसी बीमारियां शामिल हैं। जुलाई और अगस्त के महीनों में मच्छर के काटने से होने वाली बीमारियों को दावों में तेजी आती है। साथ ही गंदे पानी से होने वाली पेट की बीमारियों के लिए भी हेल्थ इंश्योरेंस के दावे बढ़ जाते हैं। इसी तरह सर्दियों में ब्रोंकाइटिस या इन्फ्लूएंजा का प्रकोप बढ़ जाता है। इसमें से कई बीमारियों के सीधा संबंध गंदगी से है। यानी साफ-सफाई से इस तरह की बीमारियों और उनसे जुड़े हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम्स को टाला जा सकता है। हालांकि आंकड़े बताते हैं कि इन बीमारियों से समाज का हरेक वर्ग प्रभावित होता है।पॉलिसीबाजार की एक हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम स्टडी के मुताबिक मौसमी बीमारियों के कुल दावों में डेंगू और मलेरिया जैसी मच्छर से होने वाली बीमारियों का हिस्सा 15₹ है। इनके इलाज में आमतौर पर 50,000 रुपये से 1,50,000

रुपये तक खर्च है। जुलाई और अगस्त में इन बीमारियों से जुड़े हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम बढ़ जाते हैं। इसकी वजह यह है कि बारिश का मौसम मच्छरों के पनपने के लिए आदर्श होता है। एक और बीमारी जो मॉनसून के दौरान चरम पर होती है। वह है गैस्ट्रोएंटेराइटिस यानी पेट की बीमारी। इसके इलाज का खर्च मलेरिया जितना ही है। सीजनल क्लेम्स में इस बीमारी का हिस्सा 18₹ है। मौसमी बीमारियों के दावों में एलर्जी की हिस्सेदारी 10₹ है।

इलाज का खर्च

सर्दियों में इन्फ्लूएंजा और ब्रोंकाइटिस के कारण दावों की संख्या 20₹ और 12₹ तक पहुंच जाती हैं। हालांकि इनके इलाज में 25,000 रुपये से 1 लाख रुपये तक खर्च होते हैं। पॉलिसीबाजार के हेल्थ इंश्योरेंस हेड सिद्धार्थ सिंघल ने कहा कि यदि आप विकसित देशों को देखें, तो वहां मौसमी बीमारियों की हिस्सेदारी विकासशील देशों की तुलना में बहुत कम है। भारत के मामले में गुरुग्राम जैसे देश के विकसित इलाकों में भी जल जमाव और मच्छरों के पनपने की समस्याएं हैं। इससे मच्छर के काटने से होने वाली बीमारियों से जुड़े दावों में बढ़ोतरी होती है। सिंघल ने कहा कि इन मौसमी बीमारियों से दावों की फ्रीक्वेंसी में बढ़ोतरी होती है। हालांकि, एवरेज क्लेम अमाउंट क्रोनिक बीमारियों की तुलना में बहुत कम है। वैल्यू के टर्म में देखें तो उनके दावों का हिस्सा 20₹ से कम होगा। उन बीमारियों के लिए अस्पताल में भर्ती होने के मामले बढ़ गए हैं जिनका पहले घर पर इलाज किया जाता था। उन्होंने कहा कि यह यह एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है, क्योंकि प्रोफेशनल सपोर्ट प्राप्त करना हमेशा अच्छा होता है। इससे बीमारियों से होने वाली मौतों की संख्या में कमी आती है।

स्वामी/मुद्रक/प्रकाशक सचिन बंसल द्वारा अपनी दुनिया प्रिंटर्स, 13, प्रेस काम्प्लेक्स, ए.बी. रोड, इंदौर से मुद्रित एवं 18, सेक्टर-डी-2, सांवेर रोड, इंडस्ट्रीयल एरिया, जिला इंदौर (म.प्र.) से प्रकाशित। संपादक- सचिन बंसल

सूचना/चेतावनी- इंडियन प्लास्ट टाइम्स अखबार के पूरे या किसी भी भाग का उपयोग, पुनः प्रकाशन, या व्यावसायिक उपयोग बिना संपादक की अनुमति के करना वर्जित है। अखबार में छपे लेख या विज्ञापन का उद्देश्य सूचना और प्रस्तुतिकरण मात्र है। अखबार किसी भी प्रकार के लेख या विज्ञापन से किसी भी संस्थान की सिफारिश या समर्थन नहीं करता है। पाठक किसी भी व्यावसायिक गतिविधि के लिए स्वविवेक से निर्णय करें। किसी भी विवाद की स्थिति में न्याय क्षेत्र इंदौर, मप्र रहेगा।